

(1400/SRG/MY)

1400 बजे

लोक सभा चौदह बजे पुनः समवेत हुई।
(डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी पीठासीन हुए)
 ... (व्यवधान)

1400 बजे

(इस समय सुश्री महुआ मोइत्रा, श्री गौरव गोगोई और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के
निकट खड़े हो गए।)
 ... (व्यवधान)

MATTERS UNDER RULE 377 -- LAID

1401 बजे

HON. CHAIRPERSON (DR. (PROF.) KIRIT PREMJBHAI SOLANKI): The matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House ... (*Interruptions*). Members who have been permitted to raise the matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes. ... (*Interruptions*). Only those matters shall be treated as laid down for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time. ... (*Interruptions*). The rest will be treated as lapsed. ... (*Interruptions*)

Re: Money Invested in Different Sahara Schemes

श्री अरुण साव (बिलासपुर):माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 377 के अधीन अत्यंत महत्वपूर्ण लोक महत्त्व का विषय उठाने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे लोकसभा क्षेत्र बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला पेन्ड्रा मरवाही जिले सहित छत्तीसगढ़ और देश के लाखों लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा सहारा के विभिन्न योजनाओं में, बच्चों की पढ़ाई, शादी-ब्याह, रोजगार के विस्तार आदि के लिए जमा कराये थे, परंतु आज वे अपने पैसे को वापस प्राप्त करने के लिए दर-दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। साथ ही साथ हजारों की संख्या में अभिकर्ता बेरोजगार हो गए हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि इस विषय पर संज्ञान लेकर निवेशकों कि गाढ़ी कमाई का पैसा वापस दिलाने हेतु आवश्यक पहल करें, और विवाद का निपटारा कराकर हमारे अभिकर्ताओं के भविष्य की भी रक्षा करें।

(इति)

Re: Stoppage of Trains at Dabhaura Railway Station, Rewa, Madhya Pradesh

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): रीवा जिले के डभौरा स्टेशन पर लॉकडाउन के पहले जिन गाड़ियों का ठहराव हो रहा था उनको दुबारा शुरू किया जाये एवं गाड़ी संख्या 14115 -16 अम्बेडकर नगर -प्रयागराज एक्सप्रेस का भी ठहराव डभौरा स्टेशन में शुरू किया जाये। (इति)

Re: Setting up of an X-Band Doppler Weather Radar System in Aurangabad, Maharashtra

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर): महाराष्ट्र का मराठवाडा क्षेत्र पिछले कई दशकों से मौसम की मार झेल रहा है। कभी यहाँ भयंकर सूखा पड़ता है तथा कभी यहाँ अति-वृष्टि, बाद तथा ओला वृष्टि होती है जिसके कारण न केवल हर साल किसानों की बड़े पैमानों पर खड़ी फसल बरबाद हो जाती है अपितु काफी बड़ी संख्या में जन हानि व पालतु पशुओं की मौत हो जाती है। इन सब समस्याओं का कुछ हद तक समाधान हो सकता है यदि किसानों को मौसम की सही सही जानकारी समय पर उपलब्ध हो जाए। परन्तु वर्तमान व्यवस्था के अनुसार दिल्ली स्थित मौसम विभाग द्वारा स्थानीय मौसम की जानकारी मुम्बई स्थित आबजर्वेटरी को भेजी जाती है। इसके बाद मुम्बई से यह जानकारी राज्य भर में स्थित सभी मौसम कार्यालयों को भेजी जाती है। जानकारी के इस प्रेषण में कीमती समय बरबाद हो जाता है तथा किसानों को समय पर मौसम की सही जानकारी नहीं मिलने के कारण फसलों के मामले में, जान-माल के मामले में तथा पशुओं की मृत्यु के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

हालांकि वर्ष 2015 से मौसम विभाग द्वारा मराठवाडा के औरंगाबाद स्थित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक एक्स बैंड डोप्लर रडार स्थापित करने का निर्णय लिया गया था परन्तु अभी तक प्रशासनिक विलम्ब व अनदेखी के कारण मराठवाडा में एक्स बैंड डोप्लर रडार की स्थापना नहीं हो पाई है। इस विलम्ब के कारण मराठवाडा के किसानों को जन धन तथा फसलों के मामले में हर साल भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में एक एक्स बैंड डॉप्लर लग जाने से स्थानीय मौसम की चौबीसों घंटों निगरानी संभव हो पाएगी तथा मौसम की हर तरह की जानकारी किसानों को यथासमय मिल पाना संभव हो सकेगा।

महाराष्ट्र में इस समय चार जगहों - मुम्बई, महाबलेश्वर, सोलापुर और नागपुर में डॉप्लर रडार स्थापित हैं परन्तु इनमें से किसी से भी मराठवाडा क्षेत्र के मौसम की सही सही मानिट्रिंग संभव नहीं है क्योंकि एक रडार से लगभग 500 किमी क्षेत्र की मानिट्रिंग की जा सकती है। महाराष्ट्र के मराठवाडा क्षेत्र के किसानों को मौसम की सही जानकारी के अभाव में हो रहे नुकसान से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि मराठवाडा के औरंगाबाद में एक एक्स बैंड डॉप्लर रडार शीघ्रातिशीघ्र स्थापित किया जाए औरंगाबाद के गांव पिंपलाद्री, ता0 सिलौद में अजिन्ठा लेणी परिसर में श्री आबुदास लोखण्डे इस रडार की स्थापना हेतु अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं।

अतः इस सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि किसानों को मौसम की सही सही जानकारी उचित समय पर उपलब्ध कराने के लिए मराठवाडा के औरंगाबाद में एक एक्स बैंड डॉप्लर रडार शीघ्रातिशीघ्र स्थापित करवाने की व्यवस्था की जाए। (इति)

Re: Development of Basic Amenities in Villages Adjoining International Border.

श्री देवजी पटेल (जालौर): सांचौर तहसील को दिनांक 12 मार्च 1996 को सांचौर चितलवाना सरवाना पुलिस स्टेशन के अंतर्गत स्थित क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया था। सांचौर और चितलवाना प्रखण्ड के नागरिकों के प्रवेश और निकास पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 500 मीटर से 1.5 कि०मी० की दूरी पर यह गाँव है, 10-15 कि०मी० पर गाँव तथा 15-20 कि०मी० गाँव स्थित है। इन गाँवों में मुलभूत सुविधा का नितांत अभाव है। इन गाँवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक शिक्षा, सामुदायिक केंद्र, कनेक्टिविटी, जल निकासी, पेयजल एवं संचार के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है।

अतः जालौर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे गाँवों में मुलभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राशि उपलब्ध करावे।

(इति)

Re: Need to Start Rail Services Between Mahsana to Bheeladi via Patan.

श्री भरतसिंहजी शंकरजी डाभी (पाटण): मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पाटण से भीलडी के बीच रेल कनेक्टिविटी का काम पूरा हो चुका है और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा उसका उद्घाटन भी किया गया है। अज्ञात कारणों से महेसाणा से पाटण होकर भीलडी के ५२ किलोमीटर के इस रूट पर ट्रेन सेवा आज तक शुरू नहीं गई है। उल्लेखनीय है कि इस विस्तार के लिए लोग रेल कनेक्टिविटी अपनी भूमि अधिग्रहण को राजी नहीं थे, मुझे उनको मनाना पडा था। अब इस रूट पर ट्रेन सेवा आज तक शुरू नहीं होने से लोगों में आक्रोश दिखने को मिल रहा है। अतः सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री से मेरा आग्रहपूर्ण अनुरोध है कि इस रूट पर बिना विलंब ट्रेन सेवा शुरू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(इति)

**Re: Issues Pertaining to Linking of Villages by Roads Under PMGS
Yojana.**

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 500 तक की आबादी के राजस्व गांव सड़को से जुड़े है। इसमें 2001 की जनगणना के आधार पर सड़को का निर्माण हुआ। योजना का उद्देश्य गांवो को सड़को से जोड़ने का है परन्तु ऐसे राजस्व गांव जो 2001 के बाद बने एवं उनकी जनसंख्या आज 500 से अधिक है वो तथा ऐसे राजस्व गांव जिनकी जनसंख्या 2001 में 500 नहीं थी परन्तु 2011 की जनगणना में 500 से अधिक हो गई, ऐसे राजस्व गांव सड़क से नहीं जुड़ पा रहे है। सदन के माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि वर्ष 2001 के बाद बने या जिन राजस्व गांवो की जनसंख्या 2011 में 500 से अधिक हो गई को इस योजना में शामिल करते हुये सड़को से जोड़ा जावे तथा 250 की जनसंख्या वाले राजस्व गांवो को भी सड़क से से जोड़ने की कार्यवाही अमल में लाई जावे।

(इति)

Re: Inclusion of Magahi Language in Eighth Schedule to the Constitution.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): मगही भाषा को मगधी भाषा के नाम से जाना जाता है, जो मगही का पूर्वज भाषा है, और बाद में उत्पन्न हो कर मगही के नाम से प्रचलित हुआ। मगधी भाषा भारत और नेपाल के भाग में बोला जाता है। मगही भाषा बोलने वाले लोगो (वक्ताओ) की संख्या लगभग 18 मिलियन है। यह भाषा बिहार के 8 जिलों और झारखण्ड के 3 जिलो में बोली जाती है। वर्ष 1961 के जनगणना मे 8 मगधी को हिन्दी के अन्तर्गत कानूनी रूप से अंगीकार किया गया था। ग्रामरियन कचछयानों ने मगधी भाषा के महत्व को उल्लेखित कराते हुआ लिखा है कि " यह भाषा सभी भाषाओं का बुनियाद है।" ब्राह्मणों और अन्य लोग कल्प के शुरुआत में इस भाषा को बोलते थे और सर्वोच्च एवं पूज्य भगवन बुद्ध भी मगही भाषा बोलते थे। वर्तमान मगही भाषा का विकास कब हुआ, अज्ञात है, परन्तु भाषा विशेषज्ञों ने मगही भाषा का विकास 8 से 11 वी सेंचुरी माना है। शिशुनाग वंश ने 8 मगध वंश को स्थापित किया। मगध वंश का भारत में शासन 684 BC से 320 बी.सी. तक का उल्लेख हैं जिसका वर्णन रामायण और महाभारत में भी है। मगध के गुप्त वंश और मौर्य वंश के द्वारा भारत के प्राचीन इतिहास को स्थापित करने के लिए विभिन्न भाषाओं का विकास किया। मगध साम्राज्य के अन्तर्गत ही अधिकांश लोगो द्वारा मगही भाषा का प्रयोग किया जाता है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि देश एवं विदेश के बिभिन्न भागों में बोले जाने वाली मगही भाषा को संविधान के 8 वी अनुसूची में जोड़ने की कृपा की जाय।

(इति)

Re: Need to Construct Overbridges at Railway Crossing No. 10 and 13 in Madhubani, Bihar.

श्री अशोक कुमार यादव (मधुबनी): मेरा संसदीय क्षेत्र मधुबनी (बिहार) जो कि यह जिला मुख्यालय भी है तथा इसकी आबादी बहुत ही घनी है। मधुबनी स्टेशन के दोनों तरफ पूरब एवं पश्चिम में सरकारी कार्यालय, मंडल कारा, हॉस्पिटल एवं शिक्षण संस्थान हैं। दरभंगा-मधुबनी-जयनगर रेल खंड में लम्बी दूरी एवं पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन अधिक है। जिसके कारण मधुबनी शहर के दोनों तरफ की रेलवे कासिंग संख्या 10 एवं 13 प्रायः बंद रहती है जिसके कारण आम लोगों को काफी परेशानी होती है। बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंच पाते हैं।

अतः आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से आग्रह है कि उपरोक्त दोनों रेलवे कासिंग पर ओवर ब्रिज निर्माण के लिए यथाशीघ्र विभाग को निर्देश देने की कृपा करेंगे। (इति)

Re: Demand for a separate State for Darjeeling hills

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): People from Darjeeling hills, Terai and Dooars have long struggled for establishing a separate 'Gorkhland' state under the constitution of our nation resulting in many agitations.

The demand for Gorkhland is directly linked to 'identity crisis' faced by the Indian Gorkhas.

To cater to the demand, two semi-autonomous bodies were established – DGHC in 1988, and GTA in 2011. However, these stop-gap experiments have failed to address the aspirations of the people.

Since Independence, Gorkhas have allegedly faced exploitation and injustice in WB. People have been allegedly deprived of their constitutional rights in the region and our region is backward due to alleged discriminations meted out by succeeding WB Governments.

Peaceful and developed critical 'chicken-neck' region is vital from the National Security perspective too.

I thank the Union Home Ministry for initiating tripartite talks to find Constitutionally Guaranteed permanent solution for our region. I request for expediting the process.

Kindly do the needful at your end.

(ends)

Re: Regulating the Running of Pre-Primary Schools in the Country.

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत में प्री-प्राइमरी स्कूल के शुरू करने एवं संचालित करने के लिए कोई विशेष संशोधित कानून बनाई जानी चाहिए। इन स्कूलों में 3 वर्ष से 6 वर्ष के छोटे-छोटे बच्चे पढ़ते हैं और इनके भविष्य की शिक्षा का आधार इन्हीं स्कूलों में तैयार होता है। यदि हम छोटे बड़े शहरों में जाए तो इस तरह के प्री-प्राइमरी स्कूल बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। इन स्कूलों में बच्चों के मार्गदर्शन हेतु सरकार को उचित कानून बनाने की आवश्यकता है। सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि प्री-प्राइमरी स्कूल को भी सरकारी संगठनों से पंजीकरण कराने की आवश्यकता हो। इससे इन स्कूलों की जिम्मेवारी बढ़ेगी और शिक्षा के प्रति अधिक सजग रहेंगे। कई बार देखा गया है कि बड़े एजुकेशन ग्रुप जो इन स्कूलों के लिए फ्रेंचाइजी देते हैं उनमें फीस लेने की भी कोई सीमा निर्धारित नहीं की जाती है। कई स्थानों में डे-बोर्डिंग की व्यवस्था है जिसमें बच्चों को नाश्ता और खाना दिया जाता है। कई बार सुनने में आता है कि बच्चे स्कूल का खाना खा कर बीमार पड़ गए हैं। मेरी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि प्री-प्राइमरी स्कूल को शुरू करने, संचालित करने, फीस और डे-बोर्डिंग है तो उसके तहत सरकार एक विशेष कानून बनाएं जिसमें व्यवस्था हो कि जो प्री-प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं वह सरकार के नियमों के तहत संचालित हो और बच्चों के भविष्य को एक नया आधार मिले। अच्छा होगा यदि नई शिक्षा नीति के तहत शामिल कर लिया जाए और पूरे देश में एक जैसा कानून हो।

(इति)

Re: Issues Pertaining to Implementation of National Water Mission.

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर): अध्यक्ष महोदय, 'राष्ट्रीय जल मिशन योजना' जो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य देश में प्रत्येक नागरिक को पीने का पानी नल के द्वारा सुगमता से उपलब्ध कराना है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश शुरू से ही जल संकट का सामना करता आ रहा है जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान राशि 10180.50 करोड़ रुपये का भी अभी तक उपयोग नहीं हो पाया है। राजस्थान प्रदेश में जल मिशन योजना में हर घर में जल कनेक्शन के तहत 150 करोड़ की धनराशि जारी की गई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं का समय पर विभागीय आंकलन करके कार्य में विलंब को दूर किया जाये। राष्ट्रीय जल मिशन योजना देश के हर नागरिक के लिए उपयोगी साबित होने वाली योजना है जिस पर समय पर कार्य किया जाना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि राष्ट्रीय जल मिशन योजना जो देश के लिए अत्यंत उपयोगी है। योजना का कार्य समय पर शुरू किया जाये जिससे कि प्रदेश की जनता को इसका लाभ समय पर मिल सके।

(इति)

Re: Alleged Theft of Coal in Jharkhand.

श्री जयंत सिन्हा (हजारीबाग): हमारा झारखंड राज्य कोयला समृद्ध है किन्तु अब यहाँ कोयला चोरी की घटनाएं आम बात हो गई हैं। मैं राज्य के सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक को संरक्षित करने में राज्य सरकार की कथित विफलता और निष्क्रियता की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। झारखंड में काम कर रही कोयला खनन कंपनियां खनन स्थलों से और परिचालन के दौरान लगातार होने वाली कोयला चोरी की घटनाओं से पीड़ित रही हैं। अकेले 2019-20 में, इन कंपनियों द्वारा झारखंड में 100 से अधिक एफआईआर दर्ज की गईं, जो कोयला चोरी के मामलों की गंभीरता को दर्शाता है।

पिछले 3 वर्षों में, 2017 और 2020 के बीच, छापे से बरामद कोयले की मात्रा में 15% की वृद्धि हुई है। चोरी में बरामद होने वाले कोयले का मूल्य ₹12 करोड़ से अधिक है। कोयले की चोरी से राज्य को महत्वपूर्ण संसाधनों का और खनन कंपनियों को भारी राजस्व का नुकसान हुआ है। एक तरफ केंद्र सरकार द्वारा CMSMS के रूप में कोयला चोरी को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। किंतु दूसरी ओर झारखंड सरकार ने राज्य में कानून-व्यवस्था से जुड़े इस गंभीर मुद्दे को हल करने के लिए अपनी ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

(इति)

Re: Shifting of a Toll Plaza.

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): मेरे संसदीय क्षेत्र बालाघाट के अंतर्गत सिवनी से छिंदवाड़ा होकर मुलताई रा.रा.मार्ग क्रं.347 है। सिवनी से छिंदवाड़ा की बीच की दूरी 70 कि.मी. है जिसमें 20 कि.मी. मार्ग सिवनी जिले की सीमा तथा 50 कि.मी. मार्ग छिंदवाड़ा जिले की सीमा में आता है। वर्ष 2016 में NHAI द्वारा टोल सिवनी से मात्र 14 कि.मी. दूरी पर ग्राम फुलारा में लगाया गया है। फुलारा के आगे सिवनी जिले की सीमा तक आने वाले लगभग 30-40 ग्रामों के नागरिकों को स्कूल कॉलेज, आफिस, ईलाज, कचहरी एवं बाजार प्रतिदिन सिवनी मुख्यालय आना जाना पड़ता है और उन्हें टोल का भुगतान करने के लिए बाध्य होना पड़ता है जिससे नागरिकों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। जिले की सीमा के भीतर यात्रा करने के लिए भी टोल का भुगतान करना मजबूरी हो जाती है। टोल स्थापित होने के बाद से ही इसका विरोध किया जाता रहा है, लगातार विरोध के बाद भी इसे हटाया नहीं गया है, इससे जनता में काफी नाराजगी है। सिवनी छिंदवाड़ा रा राजमार्ग पर NHAI द्वारा जिला मुख्यालय से मात्र 14 कि.मी. की दूरी पर फुलारा में टोल को फुलारा से हटाकर सिवनी छिंदवाड़ा जिले की सीमा में स्थापित कराये जिससे स्थानीय नागरिकों को राहत मिल सके।

(इति)

Re: Creation of a new Railway Division at Badarpur, Karimganj, Assam

SHRI KRIPANATH MALLAH (KARIMGANJ): I have the honour to draw your kind attention and personal intervention towards the very old public demand for creation of a new Railway Division at Badarpur in the district of Karimganj, Assam in my constituency karimganj. In my opinion, one new Division at Badarpur is necessary as the Lumding Railway Division was created long back perhaps in the year 1969. During the last forty years, Railway lines have been expanded to Tripura, Mizoram and being extended to Manipur. Number of passengers and goods trains have also considerably increased. In view of the above, I urge upon the union minister to kindly look into the matter and make necessary arrangements to materialise the long pending public demand of Karimganj.

(ends)

Re: Need to Secure the Financial Security of Workers Rendered Jobless After Closure of Companies in Bharuch, Parliamentary Constituency.

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरुच): गुजरात में मेरे संसदीय क्षेत्र भरुच क्षेत्र भरुच के अंतर्गत दहेज, झगड़िया, अंकलेश्वर और पानौली आदि औद्योगिक क्षेत्र हैं। यहां पर कई कम्पनियों के बंद हो जाने से वहां के कामगारों की हालत अत्यन्त दयनीय हो गई है। उद्योग शुरू करते समय उद्योगपति सरकार की योजनाओं का पूरा फायदा उठाते हैं और उसके बाद में 25-30 साल बाद कोई न कोई बहाना बनाकर तथा वही उद्योग दूसरे राज्य में लगाने तथा सरकारी फायदा लेने के लिए बन्द कर देते हैं। इस तरह से 25-30 साल तक उक्त उद्योगों में काम करने वाले लोगों को बहुत कम 6-7 लाख रुपये देकर वी.आर.एस. देकर उनको नौकरी से बाहर कर देते हैं। इसके बाद उन कर्मचारियों को हालत बहुत दयनीय हो जाती है। इन लोगों में वो Landloser भी शामिल हैं जिन्होंने G.I.D.C. को उद्योग लगाने हेतु अपनी जमीन दी। ऐसे लोगों को बहुत कम मुआवजा मिलता है तथा नौकरी भी चली जाने के कारण उनकी हालत बहुत दयनीय हो जाती है। उपरोक्त लोगों को न्याय देने वाले प्रशासनिक अधिकारी शोषित और पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के बजाय कथित रूप से ताकतवर उद्योगपतियों का ही पक्ष लेते हैं। ऐसे में सरकार से मेरा आग्रह है कि वह ऐसे शोषित और पीड़ित कामगारों की आर्थिक सुरक्षा हेतु तत्काल ठोस कदम उठाये।

(इति)

Re: Facilities of Night Landing and Introduction of New Flights at Jagdalpur Airport.

श्री दीपक बैज (बस्तर): लॉकडाउन के बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला अंतर्गत जगदलपुर हवाई अड्डे से चुनिंदा रूटों पर पुनः नागरिक विमानों का संचालन प्रारंभ हुआ है। यात्रियों और पर्यटकों की संख्या व सुविधाओं को देखते हुए इस एअरपोर्ट से अन्य शहरों हेतु विमानों के संचालन की आवश्यकता है।

इन नए रूटों पर (1) कोलकता- झारसुगुड़ा-जगदलपुर- विशाखापट्टनम (2) बेंगलूरु-विशाखापट्टनम-जगदलपुर (3) भूवनेश्वर-जगदलपुर-विशाखापट्टनम-हैदराबाद (4) नागपुर-जगदलपुर-विशाखापट्टनम पर फ्लाइटें संचालित करने से यात्री और एविएशन को फायदा होगा और एअरपोर्ट प्रारंभ करने का उद्देश्य भी पूरा होगा।

साथ ही एयरपोर्ट की सुविधाओं में इजाफा करने की आवश्यकता है। जगदलपुर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की व्यवस्था नहीं है। इससे रात में कोई भी फ्लाइट या हेलीकाप्टर न तो उतर सकता है और ना ही उड़ सकता है। जगदलपुर एअरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। मेरी मांग है कि नाइट लैंडिंग और उपरोक्त नए रूटों पर फ्लाइटों का संचालन जगदलपुर एयरपोर्ट से अविलम्ब प्रारंभ किया जाए।

(इति)

Re: Modernization and upgradation of railway stations under Adarsh Station Scheme

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): I would like to raise matter regarding modernisation/upgradation of three Railway Stations belongs to my Constituency Thalassery, Vadakara and Koyilandy stations under Adarsh Station Scheme. 1) Thalassery Railway was established during the British Period. This station is situated in the vast area of land have extend upto 50 acres and also Kannur International Airport is 25 KM away from Thalassery Railway Station and well connected with wide spacious road. Kannur. Many basic amenities required this Station and also two Flat form without roofing. 2) Vadakara Railway Station development work is very slow and basic amenities are very poor in the railway station.3) Koyilandy Railway station is also one of the important station without proper passenger amenities. I therefore request to the Hon'ble Railway Minister for upgradation and modernization under Adarsh Scheme in the above railway Stations.

(ends)

Re: Including Surjapuri community of Bihar in extremely backward category of State list and Central OBC list

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): The Surjapuri community of the Kishanganj district of Bihar is socially and economically very backward. It is present in four districts of Kishanganj, Araria, Purnia and Katihar. Currently they are being recognized in the more backward [BC-2] category of the OBC list acknowledged by the Bihar Government.

Due to lack of education and employment opportunities, this community has been socially and educationally backward since years. Majority of the population is dependent on Agriculture for their livelihood. They do not get their due representation in the educational & employment sectors of the country which is the need of the hour.

This affected community requires urgent attention and inclusion in the Extremely Backward [BC-2] category of the OBC list recognized by the Bihar Government and in the Central OBC list recognized by the Central Government as other communities with similar socio-economic background have been included in the extremely backward category of the State OBC list and Central OBC list.

(ends)

Re: Constructing underpass to NH 209

SHRI P. VELUSAMY (DINDIGUL): In Dindigul district, near Ottanchatram the NH 209, 4 lane National Highway passes through Chinnakampatti, Chinakarttupatti and Peria Kottai villages. The national highway crosses the village road and one of the main roads for the buses to these villages. The entire population of these three villagers has to cross the national highway No: 209 (Dindigul – Pollachi). I request you to provide Small Vehicular Underpass (SVUP) below the national highway 209.

(ends)

Re: Problems being faced by Tobacco dealers

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): I want to raise the voice of tobacco dealers in this august house. Tobacco dealers are basically from agricultural families and belong to rural areas. They fall under "MSME" category. Earlier there were hundreds of tobacco dealers which is now falling down to two digit due to difficult and adverse trade conditions.

They are looking for support from Tobacco board, Banks, Exporters and Ministry of Finance. If helping hand is not given to them, tobacco dealers will vanish from the Trade due to current crisis. They are requesting for following reliefs:

1. Waiver of Interest on Loans due to losses in Tobacco business in view of the Covid pandemic.
2. Reimbursement of interest overcharged by Banks on the loans availed by tobacco farmers. As per the sanction advise interest was 10-15 % per annum but the interest is charged around 12.50% to 13.50%.
3. Interest free Seed Capital assistance to them.
4. Some interest subvention Scheme for tobacco dealers.
5. Waiver of processing charges on the loans provided to tobacco dealers.

I request the government that requests / problems of Tobacco dealers may kindly be considered favourably and necessary steps may be taken for appropriate action in the interest of Tobacco dealers. (ends)

Re: Privatisation of public sector banks

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Bank unions under the United Forum of Bank Unions (UFBU) is on a nationwide strike on December 16 and 17 against the proposed privatisation of public sector banks (PSBs). Close to 9 lakh employees of PSBs like State of India (SBI), Punjab National Bank (PNB), Central Bank of India are on a two-day strike. These unions are protesting against the government's intent to privatise two public sector banks (PSBs). The government has planned to bring the Banking Laws (Amendment) Bill, 2021 during the ongoing Parliament session. The AIBEA reiterated its stand that if the government would assure that the Bank Privatisation Bill (Banking Laws Amendment Bill, 2021) would not be tabled during this session of the Parliament, we would be inclined to reconsider the strike but the government could not give any such assurance to them and the unions were forced to go on strike. The Union said that if PSBs are privatized then bank branches in rural and backward regions will be closed and implementation of all government schemes meant for EWS (economically weaker sections) will be affected. I urge upon the government to consider the genuine demands raised by bank employees' unions to avoid a strike. (ends)

Re: Grant of approval for the development of BDD Chawls existing on the MbPT land at Sewri

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): In Mumbai, there are four clusters of BDD Chawls namely Worli, Naigaon, N. M. Joshi Marg & Sewri. A total of 217 buildings were raised on 92.70 acres of land in the year 1920 by Bombay Development Board and hence are known as BDD Chawls. Since these buildings are 100 years old & are in dilapidated conditions, the Govt. of Maharashtra has decided to redevelop these buildings. Govt. of Maharashtra took the onus of development of these buildings through MHADA, a Govt. Authority and offered the resident a new home having the carpet area equivalent to 640 sq. ft. free in place of present 160 sq ft room i.e., on ownership. The project has been launched and the work is in progress. The scheme will be made applicable to all BDD Chawls clusters except Sewri as the Ministry of Shipping has not granted the approval till date. It is really unfair and unjustified as these residents are being deprived of their legitimate right to get the free house having 640 sq ft area. These buildings are on the land of MbPT which is under the control of the Ministry of Shipping. What is required is approval of the Shipping Ministry for development which is being carried by the Govt. of Maharashtra & not by private developer and where Shipping Ministry do not have to incur any expenditure. Moreover, it is in tune with the Hon'ble Prime Minister's dream to provide a Pucca Ghar to every household. Hence, I request the Ministry of Shipping to grant the approval to Govt. of Maharashtra for the development of BDD chawls existing on the MbPT land at Sewri.

(ends)

Re: Third line Commissioning in Chhapra

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): सदन के माध्यम से तीसरी लाइन की Commissioning (छपरा) जो सालों से टाली जा रही है इससे नुकसान सीधे गोरखपुर जिले से लेकर कुशीनगर, गोपालगंज, महाराजगंज जैसे उ०प्र० और बिहार के सीमांत जिलों के साथ सिवान, छपरा की लाखों जनता झेल रही है। अगर यह काम समय पर हो गया रहता तो आज जिस बजट में होगा उससे कम से कम दस गुने सस्ते बजट में निपट गया होता और तब से अब तक इस सेक्शन से रेलवे रेवेन्यू में भी करोड़ों की आय होती। यह कहा जा रहा है कि कथित प्राइवेट ट्रांसपोर्ट लॉबी की वजह से यह कार्य देरी से हो रही है।

महोदय, तीसरी लाइन Commissioning जब तक मंत्रालय की तरफ से टारगेट नहीं दिया जाएगा, तब तक यह काम नहीं होगा (क्योंकि पहले से ही जो इस स्थिति से कथित आर्थिक लाभ उठा रहे हैं उनका कहना है कि कुछ भी हो जाए 2024 से पहले Commissioning नहीं होगी।) माफियाओं का कथित सिन्डीकेट को तोड़ते हुए एवं लाखों जनता के हित देखते हुए छपरा की तीसरी लाइन की के होली तक हो जाती है तो सरकार को काफी रेवेन्यू प्राप्त होगा।

अतः मैं इस सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से यह आग्रह करता हूं कि छपरा के तीसरी लाइन Commissioning में हो रही विलंब पर जिम्मेदारी तय करते हुए 2022 के होली तक तीसरी लाइन Commissioning करने के लिए छपरा रेलवे के जी.एम. और Commissioning डिपार्टमेंट को आदेश जारी किया जाये (इति)

Re: Employment opportunities provided by Mahanadi Coal Limited, Talcher
SHRI MAHESH SAHOO (DHENKANAL): Talcher and its adjoining areas produce 30% of total coal output in the country. Having said that, one must also note that employment opportunity in Mahanadi Coal Limited is very low when compared to other coal producing locations.

Mahanadi Coal Limited in Talcher employs only twenty-one thousand people whereas, coal field in Bihar, Jharkhand and West Bengal employ much higher in number close to one lakh at each location. Employment in fewer number for performing similar amount of work means that the workers are either over loaded when output is more or the output has been compromised by employing fewer number of workers. Employing more workers by MCL will negate both the challenges.

There is opportunity for MCL to give employment to more than 5000 people from the locality. If employment is provided, production and performance of MCL will improve. Above all, the problem of unemployment in Talcher and adjoining areas will also be taken care of for a long period of time to come. Further, people will be benefited to a larger extent. Therefore, I urge upon the Minister of Coal to consider the matter with compassion at the earliest. (ends)

Re: Alleged irregularities in implementation of PMGS Yojana in Amroha Parliamentary Constituency.

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): मेरे संसदीय क्षेत्र अमरोहा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत बन रहे सड़कों को मानक के अनुरूप नहीं बनने एवं अनियमितता की शिकायतें मुझे प्राप्त हुई हैं। जिस में जनपद अमरोहा एवं हापुड़ में पीएमजीएसवाई-3, बैच-1 के अंतर्गत निम्नलिखित मार्ग शामिल हैं।

1. ब्लाक-अमरोहा पैकेज सं०- UP 3566, मार्ग- खेडा अप्रौला से जमना खास वाया मिठनपुर,
2. ब्लाक-हसनपुर पैकेज सं०- UP 3570, मार्ग- बी०बी०बी मार्ग से भवालपुर,
3. ब्लाक-अमरोहा पैकेज सं०- UP 3571, मार्ग- अमरोहा नूरपुर से गजस्थल,
4. ब्लाक-जोया पैकेज सं०- UP 3573 मार्ग- चौधरपुर से अमरोहा वाया साहसपुर वाया मिलक कटाई।
5. ब्लाक- सिम्भावली, पैकेज सं०- UP 7116 मार्ग- किठोर हापुड़, मुदाफरा से वाया वीरसिंहपुर, दितियाना, फुल्डेहरा वाया सिम्भावली।
6. ब्लाक-गढ़मुक्तेश्वर, पैकेज सं०- UP 7117 मार्ग शाहपुर चौधरी से वाया दौताई, अठरौनी हसुपुर मार्ग

अतः सरकार से मेरी मांग है की इन सड़कों में हो रही अनियमितताओं की जाँच विशेष टीम द्वारा शीघ्र कराई जाय ।

(इति)

Re: Expeditious completion of stretch of NH 48

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल (सतारा): मेरे लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पुणे - सातारा सेक्शन का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इसे जल्द से जल्द पूरा करने की आवश्यकता है । इस सेक्शन में बने हुए रोड पर जगह जगह पर गड्डे पड़े हैं। इस के चलते दुर्घटना होने की संभावना है । वेळे गांव के पास बनने वाली दोनों सुरंगों का काम अभी पूरा नहीं हुआ ।

(इति)

Re: Operationalisation of AIIMS in Madurai

SHRI S. VENKATESAN (MADURAI): In Jan 2019 Hon'ble PM laid the foundation stone of AIIMS, in my Madurai Constituency TN. Now, the Hon. Health Minister has said that it is going to be completed in 2026, and the ministry is going to take temporary accommodation of Government colleges to teach the students. It is very unfortunate to hear that the building would be completed only in 2026.

I would request the Hon'ble Minister to kindly share the following details;-

When do you propose to start the construction work of AIIMS in Madurai and by when is it likely to be completed?

When is the admission process likely to start in AIIMS Madurai along with the proposed date of opening of the prestigious institution in Madurai, Tamil Nadu?

(ends)

अनुपूरक अनुदानों की मांगे - जारी

माननीय सभापति: अनुदानों की अनुपूरक मांगे।

***श्रीमती रंजनबेन भट्ट (वडोदरा):** आदरणीय सभापति जी, मेरे सादर नमस्कार मैं सपलीमेंट्री ग्रांट की चर्चा में भाग लेते हुए आप के माध्यम से इसका समर्थन करती हू। जिस प्रकार कोरोना की बीमारी पूरे विश्व में हाहाकार मचाया और वहाँ के लोगो की जान ली लेकिन हमारी सरकार ने कोरोना के प्रभाव को कम करने की जो व्यवस्था बनाई वह प्रशंसनीय है। चाहे अस्पतालो में डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारियो की व्यवस्था हो या दवाइया , ऑक्सीजन की आपूर्ति या अम्ब्युलंस हो। बीमार व्यक्तियों के लिए सुचारु रूप से पूरी की गई जिसकी वजह से काफी लोगो की जान बचाई जा सकी है। एक ओर जहाँ हमारी सरकार यह व्यवस्था कर रही थी वही दूसरी ओर कोरोना के प्रभाव को समाप्त करने के लिए वेकसिन तैयार करने का कार्य भी कर रही थी, इसी लिए इतने कम समय में हमारे देश में वेकसिन बनकर तैयार की गई की अपने देश की मांग तो पूरी हुई ही साथ ही विदेशो में भी भेजी जा सकी। हमारी सरकार भविष्य में डॉक्टरों की कमी न हो इसके लिए देश के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय भी लिया और इस कार्य को तेजी से क्रियान्वित भी कर रही है। हमारी सरकार केवल मेडिकल कॉलेज ही नहीं देश के विभिन्न भागो में अस्पतालो की भी स्थापना तेजी से कर रही है, केवल अस्पताल ही नहीं बल्कि अखिल भारतीय इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट की भी स्थापना करने जा रही है, ताकि सभी लोगो को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध हो सके। हमारी सरकार केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि रेलवे में ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर तथा गति बढ़ाकर के लोगो को सुविधा प्रदान करने का कार्य तो कर ही रही है वही देश के कई रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यकरण व सफाई व्यवस्था का कार्य भी तेजी से कर रही है। देश के कई रेलवे स्टेशनों पर सरकार यात्रियों के लिए मुफ्त वाई फाई की सुविधा भी प्रदान कर रही है , देश के सभी लोगो का स्वास्थ्य बना रहे उसके लिए हमारी सरकार गाँव व शहरों की सफाई का काम भी तेजी से कर रही है ताकि लोगो को बीमारियों से बचाया जा सके और उनका धन व समय भी बच सके। हमारी सरकार गाँव गाँव में स्वच्छ पीने के पानी की भी व्यवस्था कर रही है, लोगो को नल से पीने का स्वच्छ पानी मिलने से उनके स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। हमारी सरकार देश के गरीब लोगो को मुफ्त राशन वितरित कर रही है ताकि हमारी सरकार में किसी को भी भूखा न सोना पड़े और सभी के साथ न्याय हो सके , हमारी सरकार ने करीब **80** करोड़ लोगो को प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन वितरित किया है। हमारी सरकार ने नयी शिक्षा नीति लागू करके देश के छात्रों को कई सुविधाएँ उपलब्ध कराने का कार्य किया है। हमारी सरकार ने कौशल विकास लागू करके देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है, पहले युवाओं को मात्र नौकरी ही एक सहारा था किन्तु आज युवाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए अनेक रास्ते खुल गए हैं। अब युवा स्वयं आत्मनिर्भर हो ही रहे हैं एवं दूसरे के जीवन यापन का सहारा भी बन रहे हैं। उक्त सभी कार्यों के होने के कारण निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा, यह सभी कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास से संभव हो पा रहे हैं। अतः मैं इसका तहे दिल से समर्थन करती हूँ।

(इति)

***डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज):** धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे Supplementary Demand for Grants for 2021-22, 2nd Batch पर अपनी बात रखने का मौका दिया। वर्तमान विधेयक जोकि एग्रोप्रोप्रेशन बिल है जिसमें हम सब 3,73,761 करोड़ पर चर्चा कर रहे हैं। इस विधेयक के पास होने से देश की आर्थिक विकास में गति आएगी तथा सभी छात्रों में बराबर विकास होगा।

महोदय, मई 2020 में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की घोषणा सरकार ने की थी ताकि आत्म निर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत विकास की गति में तेजी आए। इसके साथ-साथ में यह कहना चाहूंगा कि आत्मनिर्भर भारत योजना- आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के रूप में सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ नए रोजगार के सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के साथ कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की ढाणी के प्रतिस्थापित हेतु 1 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ की गई थी। देश में विकास के लिए सरकार रेगुलर रूप से आत्मनिर्भर भारत के द्वारा उठाए गए कदम को Financial Year 2020-21 में Progress की मापदंड देख रही है तथा विकास की गति को आगे बढ़ा रही है। सरकार छोटे छोटे लघु उद्योगों को मजबूती दे रही है उसको Financial Support दे रही है ताकि देश में रोजगार का सृजन तो अधिक से अधिक लोगों को आत्मनिर्भर पैकेज से फायदा हो।

महोदय, इस बिल के पास होने से आर्थिक मजबूती बढ़ेगी अगर हम रेलवे का उदाहरण उठाएं तो हम देखते हैं कि भारतीय रेल Largest Transporter देश की है और भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास दर को बहा रही है कोविड-19 के बावजूद रेलवे ने देश में Freight Loading पिछले साल की तुलना में बढ़ी है। Coaches, Locomotives और Wagons के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। अतः हम कह सकते हैं कि Railway are actively contributing in growth of Indian Economy.

महोदय, मैं Supplementary Demand for Grants for 2021-22 इस सदन में लाया गया है और इस पर लाभदायक सुझाव भी आए हैं। सरकार में खाद पर 58,430 रुपये का Subsidy के Approval का प्रस्ताव रखा है जो कि किसानों के लिए आवश्यक है ऐसा इसलिए किया गया कि अंतरराष्ट्रीय पटल पर Raw Material की कीमत में बढ़ोतरी हुई है इस विधेयक में सरकार ने 53,123 करोड़ रुपए का Approval Seek किया गया ताकि Pending Export Incentives को सुदृढ़ किया जा सके। इस विधेयक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 49000 करोड़ रुपया वित्त मंत्रालय ने अलग-अलग स्कीम जो कि फूड स्टोरेज और Warehousing से संबंधित है का प्रावधान रखा है जिससे इस क्षेत्र में मजबूती आएगी। यह क्षेत्र विकास करेगा एवं Farmers Community और ग्रामीण क्षेत्र निश्चित रूप से मजबूत होगा।

महोदय मैं Supplementary Demand for Grants पर अपनी बात रखने के साथ-साथ इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज से कोई भी ट्रेन

महानगरों जैसे दिल्ली आदि के लिए नहीं है जिससे मेरे क्षेत्र में विकास की गति थोड़ी धीमी है क्योंकि भारतीय रेल की सेवा लोगों को नहीं मिल रही है इसलिए महोदय गोपालगंज से दिल्ली के लिए ट्रेन की सुविधा मुहैया हो ताकि इस ग्रामीण क्षेत्र का विकास बढे।

अप्रैल-अक्टूबर 2021 के आंकड़े के अनुसार, सरकार ने 12.8 लाख करोड Receipts को Collect किए हैं जोकि सराहनीय है जैसा कि Article 270-भारतीय संविधान के अनुसार Union Tax का Sharing के बारे में उल्लेख है और इस विधेयक के पास होने से निश्चित ही सभी राज्यों को खासकर बिहार को भी मजबूती मिलेगी। Special Financial Assistance to States के स्कीम से निश्चित ही राज्यों का आर्थिक गति बढेगी। Infrastructure के क्षेत्र में आवश्यक है कि अधिक व्यय हो इससे विकास की गति निश्चित ही बढेगी।

इसी के साथ साथ इस विधायक की सपोर्ट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।
धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय

(इति)

***श्री उन्मेश भैर्यासाहेब पाटिल (जलगाँव):** धन्यवाद अध्यक्ष महोदय की आपने मुझे Supplementary Demand for Grants पर बोलने की अनुमति दी। मैं सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री निर्मला जी भगवत कराड जी और पंकज चौधरी जी का अभिनन्दन करता हूँ की आज उन्होंने संसद के समक्ष 3,73,761 crore का Second batch of Supplementary Demands for Grants for 2021-22 जिसमे 69 Grants and 2 Appropriation है जिसमे से net cash outgo 2,99,243.04 crore है।

इस रविवार को जब मैं TV देख रहा था तो मेरा मन हुआ Comedy movie देखने का और संजोग से उसी दिन news channels पर कांग्रेस पार्टी की महंगाई बचाओ रैली आ रही थी जिसमे उनके युवा नेता हिन्दू और हिंदुत्व का फर्क बता रहे थे और अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव है तो यह स्पष्ट है की RELIGIOUS TOURISM शुरू हो जाएगा लेकिन इतिहास इस बात का प्रमाण है की कैसे कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृति नहीं दी थी।

यही नेता शिव भक्त और जनेऊधारी भी थे कुछ वर्ष पहले। हमारे प्रधानमंत्री जी ने काशी corridor जैसे महत्वकांशी परियोजना को पूरा किया जिससे वहा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और 40 ancient temples were rediscovered during the work on the project. मैं उम्मीद करता हूँ की शिव भक्त युवा नेता इस कार्य के लिए सरकार का अभिनन्दन करेंगे क्योंकि काशी विश्वनाथ भगवान शिव का स्थान है।

हमारे विपक्ष के नेता अधीर रंजन जी ने तो राहुल गाँधी को ही digital क्रांति लाने का श्रेय दे दिया। मैं उनकी बात से सहमत भी हूँ क्योंकि राहुल जी ने डिजिटल क्रांति लाई है अपने twitter अकाउंट के माध्यम से जहा उन्होंने भारत का नक्शा ही गलत tweet कर दिया था और उन्हें उसे delete करना पड़ गया।

आज यही कांग्रेस पार्टी और महा विकास आघाडी सरकार के शासन में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कृषि मज़दूरों ने आत्महत्या की है NCRB की रिपोर्ट के अनुसार FDI में महाराष्ट्र सबसे आगे रहता था लेकिन RBI's data के अनुसार Maharashtra had slipped to the 3rd spot in attracting FDI after Gujarat and Karnataka. हम FDI में पिछड़ गए क्योंकि महाराष्ट्र सरकार FDI नहीं extortion और वसूली में ही व्यस्त थी।

महाराष्ट्र में आज अस्पतालों में आग लगने की खबरे आ रही जिसमे कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, आज महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है की पशुओं के लिए दिए जाने वाले घेरान भी divert करके किसी third party को दिए जा रहे है। मराठा समाज के साथ भी ये सरकार ने अन्याय किया और उनको दिए जाने वाले आरक्षण से वंचित रखा गया है जबकि केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन करके राज्य सरकारों को अधिकार दिया है obc लिस्ट बनाने का।

कोरोना महामारी के दौरान हमारी सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया, निर्मला जी ने Rs. •6,28,993 crore के relief package की भी घोषणा की है जिसमे

- Rs 1.1 lakh crore loan guarantee scheme for COVID affected sectors
- Additional Rs 1.5 lakh crore for Emergency Credit Line Guarantee Scheme
- Credit Guarantee Scheme to facilitate loans to 25 lakh persons through Micro Finance Institutions (MFIs)
- Financial support to more than 11,000 Registered Tourists/ Guides/ Travel and Tourism Stakeholders
- Free one month Tourist Visa to first 5 lakh tourists
- Extension of Aatma Nirbhar Bharat Rozgar Yojana till 31st March 2022
- Additional subsidy of Rs. 14,775 crore for DAP & P&K fertilizers
- Extension of Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) – Free food grains from May to November, 2021
- Rs. 23,220 crore more for public health with emphasis on children and paediatric care/paediatric beds

आज भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है और मुझे विश्वास है की हम 5 trillion dollar की अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य प्रधान मंत्री जी ने रखा है उसको हम पूरा करेंगे।

कोरोना महामारी से जो विश्व भर में आर्थिक नुकसान हुआ है उसके बाद भी India registered its highest ever annual FDI inflow of US\$ 81.97 billion in the financial year 2020-21 despite the COVID related disruptions. हमारी सरकार में महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है और राजनीतिक सशक्तिकरण के अलावा आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण भी किया गया है। Out of the 58,000+ DPIIT recognised startups, 46% of them have at-least one-woman director. Further, under Startup India Seed Fund Scheme (SISFS), as on 06th December, 2021, 55 women led startups have been sanctioned financial assistance.

कृषि क्षेत्र में innovation और start up को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने 646 start-ups in the agriculture and allied sectors have been selected under "Innovation and Agri-Entrepreneurship Development" for funding of a sum of Rs. 69.92 crore. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि में total of Rs. 1.6 lakh crore have been released so far to more than 11.5 crore farmer families.

हमारी सरकार ने किसानों के विकास के लिए paddy पर दी जाने वाली MSP को बढ़ाकर Rs. 1868 per quintal कर दिया है जो Rs. 1310 per quintal थी 2013-14 में और इसमें 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और गेहू की MSP Rs. 1400 per quintal से Rs. 1975 per quintal तक बढ़ा दी गयी है। 11 करोड़ से अधिक किसानों को soil health card issue किया गए है और "Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY)" में organic farming को प्रोत्साहन देने के

लिए 19043 clusters बनाये गए है जिससे 3.81 lakh ha has been covered और 9.52 lakh किसानों को इससे फायदा हुआ है।

ये सभी आंकड़े हमारे प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री जी के प्रयासों का परिणाम है और पूरे देश को विश्वास है की सरकार अर्थव्यवस्था और समग्र विकास पर निरन्तर काम करती रहेगी और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास की जो विचारधारा है उस पर हम कार्य करते रहेंगे।

मंत्री जी और सरकार के समक्ष अपने राज्य और लोक सभा क्षेत्र से सम्बंधित कुछ मांगे रखना चाहूंगा -

1. Padalse and Seven Ballon Barrage

The Padalse Project on the Lower Tapi will provide irrigation and drinking water supply to nearly 60 villages in Amalner taluka and Jalgaon and Dhule district. Seven Balloons Barrage project on Girna River is crucial for catering to drinking water supply & irrigation in Jalgaon. Construction of seven Barrages with smart pneumatically operated weirs/Balloon Weirs has been given administrative approval by both Central & State Government. Farmers of North Maharashtra region have been suffering due to drought for decades now despite being one of the leading cotton and banana producers in the country. I request the Government to include Padalse Project under Pradhan Mantri Krishi Sinchayce Yojana and operationalize Seven Balloon project at the earliest which will benefit farmers and citizens in Chalisgaon, Amalner, Dharangaon, Bhadgaon, Pachora and Jalgaon and also address the problem of lack of irrigation and water supply which has caused heavy financial and emotional distress to the farmers in my constituency.

2. AMRUT 2

सरकार ने amrut 2.0 योजना की घोषणा की है जिसमे 4,700 towns / cities को 'water secure बनाने के कल्पना है'. मेरा सरकार का सुझाव होगा की इस योजना में उन शहरों को भी शामिल किया जाए जहा की आबादी एक लाख से अधिक है। इससे जो छोटे शहर है जैसे चालीसगाव अमलनेर और अन्य भी लाभान्वित होंगे।

3. Indore jalgaon pune flight

मेरा सरकार से निवेदन है की INDORE -JALGAON -PUNE की फ्लाइट की बहुत ज्यादा मांग है क्योंकि ये ROUTE औद्योगिक और शिक्षा के दृष्टिकोड से बहुत उपयोगी है और मैं निवेदन करूंगा की इसको जल्द ही शुरू किया जाए। अंत में अपनी बात मैं बशीर बद्र साहब की दो पंक्तियों से करना चाहूंगा जो हमारी कार्य प्रणाली और हमारे सरकार का मूलमंत्र है -

हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है
जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा

(इति)

***श्री गणेश सिंह (सतना): अनुदानों की पूरक मांगों का दूसरा बैच 2021-22 जो वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ।**

यह मांग 3.73761 लाख करोड़ की है। इसमें किसानों की उर्वरक सब्सिडी 58430 करोड़ का अतिरिक्त खर्च तथा नदी जोड़ो अभियान “नीरा” के लिए 4300 करोड़ का शामिल है।

इसमें 69 अनुदान मांग तथा विनियोग शामिल है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ इसलिए कि देश के करोड़ों करदाताओं द्वारा दी जा रही धनराशि का सही दिशा में हर तरह की जरूरतों को सभी के लिए सभी क्षेत्रों में सभी तरह के कार्यों को पूरी ईमानदारी से खर्च किया जा रहा है।

महोदय,

2014 के पहले कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों में

- देश को दिव्यांग बना दिया था।
- चारों तरफ निराशा का भाव था।
- भ्रष्टाचार चरम पर था तब ऐसे संकट के समय गुजरात से एक कोहिनूर चला और पूरे देश में विकास तथा आर्थिक सुधार की चादर फैला दिया।
- नोट बंदी
- बैंकों में गरीबों के खाते
- बेनामी सम्पत्ति के लिये कानून
- फर्जी कम्पनियों का अंत
- जांच एजेंसियों को स्वायत्ता देकर देश तथा दुनिया को चौंका दिया
- नोट बंदी का विरोध उन्हीं लोगों ने किया था, जिनके पास नोटों के बन्डल बड़ी मात्रा में बेनामी थे। जो लोग आधे में नई नोट लाने के लिये लोगों को लाईन में खड़ा करते थे।
- देश बदल रहा है
- आत्म निर्भरता की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है
- कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से देश को उबरने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उन्हें आने वाली पीढ़ी कभी भुला नहीं पायेगी।
- संकट के समय में मुफ्त में वैक्सीन सभी को
- देश के सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट
- अस्पतालों में सभी तरह की सुविधाएं दी गईं

- देश में जहां एक और अधोसंरचना निर्माण में

जैसे- सड़क, बिजली, सिंचाई, रेलवे, राष्ट्रीय सुरक्षा, हवाई अड्डों का विकास, एम्स अस्पतालों का निर्माण, देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने, नदियों को जोड़ने की योजना

- जिसमें केन बेतवा बुन्देलखण्ड की किस्मत बदलने वाली योजना है
- जिसमें 12 लाख हेक्टेयर में सिंचाई
- 62 लाख लोगों को पीने का पानी
- 117 मेगावाट पन बिजली
- 17 मेगावाट सौर ऊर्जा बनेगी
- इसमें 45 हजार करोड खर्च किये जायेंगे, शामिल है

दूसरी तरफ-

- गरीबों को मुफ्त में अनाज-80 करोड
- गरीबों को पक्के घर- 295 करोड
- घर-घर बिजली – शत प्रतिशत
- घर-घर नल से जल-2.86 करोड घर
- रसोई गैस – 9 करोड
- शौचालयों का निर्माण – 12 करोड
- आयुष्मान कार्ड की सुविधा – 13.44 करोड
- मुफ्त में कोविड टीका शामिल है – 150 करोड
- किसानों को सम्मान निधि – 11.23 करोड, 9 किश्त चली गई
- फसल का बीमा
- मिट्टी का परीक्षण
- पेंशन योजना
- छोटे व्यापारियों को पी०एम० स्वनिधि योजना
- राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 181101 एक लाख करोड की मंजूरी
- स्वास्थ्य के लिए 2,23846 लाख करोड जो अब तक सबसे अधिक है
- जल जीवन मिशन शहरी - 2.87 लाख करोड
- स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1,41678 करोड खर्च करने की मंजूरी

- रेलवे के लिए 1.10055 करोड़ की सहायता दी जा रही है
- आत्मनिर्भर भारत के लिए 23 लाख करोड़
- कोरोना के बाद भी 39.7 लाख लोगों को रोजगार का पैकेज मिला- 2612.10 करोड़ का भुगतान भी हुआ

संकल्प जो लिये गये हैं-

- अमृत महोत्सव
- किसानों की आय को दोगुना करना
- मजबूत अवसंरचना
- स्वस्थ भारत
- सुशासन
- युवाओं के लिए अवसर
- सभी के लिए शिक्षा
- महिला सशक्तिकरण
- समावेशी विकास
- देश की सुरक्षा सर्वोपरि, राष्ट्र पहले
- 2018 में केंद्र से सतना को मेडिकल कॉलेज मिला था 550 करोड़ की योजना थी, 300 करोड़ में भवन बन गया 250 करोड़ की अस्पताल की वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली
- सामाजिक न्याय मंत्रालय दिव्यांगों के लिए एडिप योजना चलाई जा रही है, उसमें मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल जिसकी कीमत 45000 है, उसमें मात्र 25000 की सहायता है। मेरी मांग है कि बाकी की राशि भी बजट में उपलब्ध कराई जाय।
- दो राज्यों को सड़क मार्ग से जोड़ने की जो योजना है “भारत माला” उसमें लोकसभा क्षेत्र से सतना] कोटर रीवा लोकसभा क्षेत्र से सेमरिया, सिरमौर, जवा, शंकरगढ़, प्रयागराज को जोड़ने हेतु 4 लेन सड़क की स्वीकृति दी जाए
- मेरा सतना जिला औद्योगिक जिला है, स्मार्ट सिटी भी बन रहा है एक आई०आई०टी० का शैक्षणिक संस्थान खोला जाए
- मेरे लोकसभा क्षेत्र में लंबे समय से एक सैनिक स्कूल तथा मैहर में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग है
- मैं सांसद ट्रॉफी कराता हूं 40 करोड़ की लागत से मैं एक स्पोर्ट्स काम्पलेक्स बना रहा हूं इसलिये खेल महाविद्यालय खोलने की मांग करता हूं

- हर घर में नल जल योजना के तहत सतना, रीवा, सीधी जिले की संयुक्त जल प्रदाय योजना की स्वीकृति दी जाए, डी०पी०आर सम्मिलित हो गया है
- चित्रकूट तथा मैहर दो बड़े धार्मिक स्थल हैं, यहां करोड़ों लोग आते हैं, इन्हें विशेष धार्मिक क्षेत्र घोषित किया जाए तथा मेलो को केन्द्रीय कलेण्डर में जोड़ा जाए
- किसानों की फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए खुले अभयारण्य बनाए जाएं तथा उनके लिए चारा, भूसा बैंक बनाने के लिए मनरेगा में प्रावधान किया जाए
- सतना जिले के रामगढ़ तथा घुनवारा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोली जाएं
- आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जो स्मॉल औद्योगिक इकाइयां विशेष रूप से जो प्लास्टिक पर आधारित हैं, उन्हें सरकारी खरीद में, विशेष रूप से जल जीवन मिशन में बड़ी मात्रा में उपयोग में आ रहे एसडीपी पाइप की खरीद में छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ने से नए रोजगार पैदा होंगे, साथ ही जीएसटी में भी सहूलियत दी जाए
- फुट वेयर व्यापारी जो गरीबों के लिए चप्पल, जूते बनाकर बेचते हैं उन्हें अभी 5% जीएसटी देना पड़ता था अब 15% किया जा रहा है। इससे सीधा असर गरीबों पर पड़ेगा, इसे यथावत रखा जाए
- रिजर्व बैंक में बड़ी संख्या में देशी कंपनियों ने स्मॉल फाइनेंस लाइसेंस की मांग की है, कमेटी बन गई है, किंतु पिछले 2 सालों से उन पर निर्णय नहीं किया जा रहा, इस और में ध्यान दिलाना चाहता हूं
- देशी हवाई उड़ान सेवा के तहत चयनित हवाई अड्डों से छोटे जहाज चलाने हेतु आमंत्रण दिए जाएं

(इति)

*SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): Respected Sir,

1. I support the supplementary demand for grants and take this opportunity to congratulate the Hon'ble Finance Minister, who under the guidance of our Hon'ble Prime Minister Sh. Narendra Modi ji has saved our nation from the catastrophic impact of COVID pandemic.
2. Our nation was staring economic doom due to COVID, however thanks to the visionary leadership and timely intervention of PM Modi ji and Finance Minister Nirmala Sitharaman ji through economic stimulus, today our country is soaring and has become one of the fastest growing economies in the world.
3. Thanks to their intervention, latent economic potential of our great country has been unleashed and it is well on its way to an unparalleled growth trajectory.
4. With the singular vision of transforming India by transforming our infrastructure, our government is helping usher in economic prosperity, and providing a platform for sustainable development at the grassroots level.
5. Sir, I have the privilege of representing Darjeeling constituency, and would like to highlight some of the main issues concerning our region, and request Hon'ble Finance Minister for her intervention towards resolving those.

Special Financial Package for Tourism Sector

6. Sir, Darjeeling hills, Terai and Dooars region is famous for tourism.
7. Our region attracts the largest number of tourists in the Eastern Himalayan region.
8. Tourism is the largest economic activity and the largest employment sector for the locals.
9. However, tourism sector in our region has been devastated due to COVID pandemic and indifference on the part of the West Bengal Government.
10. I request Hon'ble Finance Minister to kindly consider a special financial support package to tour, taxi, hotel, restaurant and homestay operators,

majority of whom operate Medium and Small-Scale Enterprises and have been hard hit by the COVID Pandemic and related lockdown.

Agriculture, Irrigation and Rural Development

11. Darjeeling hills, Terai, Dooars and North Bengal region is a hub of agricultural produce.
12. However, WB Govt has failed to provide due support to the agricultural sector in our region.
13. There is an acute need for the establishment of Cold Storage facilities in our region to cater to the needs of farmers, horticulturists, floriculturist who are unable to save their farm produce due to no cold chain facilities in our region.
14. I request Hon'ble Finance Minister to kindly give special financial support for entrepreneurs or SHGS/FPOS who may be willing to set up cold chain facilities in our region.
15. Since our region is contiguous to North East India, and is situated in a high mountain environment, I am requesting that entrepreneurs in our region be provided with same incentives and support as rest of North East India.

Drinking Water

16. Despite receiving high rainfall, water scarcity is the most chronic issue facing various parts of the Darjeeling Lok Sabha constituency.
17. Due to the unplanned development of urban cities and inadequate infrastructure in rural regions Traditional water sources like lakes, springs, rivers and canals are drying up.
18. While our region receives enough rain, what we lack is the resources to retain the abundant water.
19. Nearly 15Lakh people live under acute water shortage in Darjeeling, Kalimpong Kurseong Mirik. Siliguri, Matigara, Algara, Phansidewa, Khoribari, Naxalbari blocks.
20. I request the Finance Ministry to kindly allocate additional funds under Har Ghar Jal' program so that we can include rejuvenating and reviving local water bodies by introducing various water harvest spring recharging methods.

- (i) We also need to include Kalimpong, Kurseong, and Mirik Municipalities under AMRUT, and
- (ii) Develop Mahananda and Balason river front on the lines of Sabarmati River Front, so that these rivers become a tourist attraction and also promote health and wellbeing of the people from our region.

Health

21. Sir, healthcare system in entire North Bengal region is in a state of coma. We need help and financial support from the Central Government for
- i. Help construct an AIIMS in North Bengal.
 - ii. Converting Darjeeling or Kalimpong District hospitals as a Medical College.
 - iii. Establish AYUSH hospitals in the districts of Darjeeling, Kalimpong and North Dinajpur.

Education and Skills

22. Sir, my constituency Darjeeling is already a hub of education, not only in Eastern India, but also across the South and South-East Asian countries, with the first western school was established here in 1823.
23. There is immense potential in developing Darjeeling as an educational hub Therefore. I request to the Hon'ble Finance Minister to kindly allocate funds for a:
- i. Medical college in Kalimpong District.
 - ii. Central University in Darjeeling district.
 - iii. National Institute of Technology in Kurseong.
 - iv. Indian Institute of Management in Phansidewa.
 - v. AIIMS in Siliguri.

Economic Development

24. Sir, Siliguri is the most important and strategically located in all of India.
25. It lies in the heart of North Bengal and also the Chicken Neck corridor
26. Development of Siliguri as a Smart City will help our entire region.
27. I request Hon'ble Finance Minister to kindly allocate additional funds for the Smart City initiative, so that Siliguri can be developed as a Smart City.

Internet and Connectivity

28. Sir, being a mountain region, even after 75-years of Independence connectivity is a major issue in my constituency and people living in some areas do not even have basic mobile or internet connection.
29. I request the Hon'ble Finance minister to kindly allocate additional budget for our region, so that people can be provided with basic internet and connectivity.

Infrastructure

30. Sir, hundreds of villages in our region are deprived of motorable road access.
31. While tourism and business activities have grown manifold, infrastructure in our region is grossly inadequate.
32. The thrust on rural infrastructure via enhanced spending on MGNREGA, PMGSY, RIDF schemes is helping bridge the gaps in infrastructure in our region, however the pace of work is very slow, and funds sanctioned are very low.
33. Sir, since ours is strategically a very important region I request the Finance Minister to kindly allocate additional resources for Roads and Surface Transport Ministry so that they can expedite:
 - i. Construction of elevated 4-lane highway corridor connect Balason to Sevoke.
 - ii. Construct an alternative bridge over River Teesta connecting Sevoke in Darjeeling to Ellenbari in Jalpaiguri District, as the current Coronation bridge that connects Darjeeling and Sikkim to Dooars was built in 1937 and is crumbling.
 - iii. Construct a 4-lane ring-road around Siliguri city from Matigara to Fulbari, Salugara and Darjeeling more, so that traffic problem is resolved in our region.
 - iv. Construct an alternative highway connecting Darjeeling to Siliguri via Balason and Ghoom.

Airport Development.

34. Given the strategic location of Darjeeling, our region is vital to National Security.
35. Darjeeling and Kalimpong region attract the largest number of tourists in Eastern Himalaya, and Bagdogra is the only airport catering to entire North

Bengal-yet the facilities here are abysmal. Bagdogra is one of the 20 busiest airports in India.

36. On a daily basis around 35 flights land and take off from here, and close to 6000 passengers use this airport on a daily basis. This number is expected to grow by volumes in the coming days.
37. Yet, the airport infrastructure has remained unchanged over decades. Passenger services and facilities are abysmal. Because of which our region is suffering.
38. I therefore request Hon'ble Finance Minister to kindly allocate funds so that development of Bagdogra Airport can be expedited.

Development of Tea Industry.

39. Sir, Darjeeling and Tea are synonymous.
40. However, due to the apathy and indifference of the West Bengal government, our tea industry is suffering. I am therefore requesting Hon'ble Finance Minister to kindly intervene towards:
 - i. Timely Implementation of Welfare Fund Announced in 2021-22 Budget: The Union Government has announced Rs 1000 crores towards welfare of tea garden workers from West Bengal and Assam. Timely implementation of the projects under this fund, for the welfare of the tea workers will go a long way in addressing various issues they have continued to face.
 - ii. Timely disbursement of Subsidy and Other Funds: Planters in North Bengal and South India have alleged that the subsidy payments under various schemes have been skewed in favour of the tea gardens based in North East. Even though there have been some improvement in the disbursement pattern in the past year, however there is still a huge disparity in the ratio, which is still heavily skewed in favour of the tea industry in the North East, while the tea industry in North Bengal and elsewhere have continued to suffer. I request for timely disbursement of Subsidy and other funds to the tea plantations in North Bengal.

I thank you Speaker Sir, for permitting me time to put across my views on the supplementary demand for grants, and I also thank you for giving me the opportunity to apprise the House of the concerns of our region and people.

(ends)

*SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): Hon. Speaker, Sir, for the first time since Independence, under the guidance of hon. PM, Shri Narendra Modi, the thrust on the holistic development of our nation is escalating with a trajectory. It behoves me to mention that "History tells us that powerful people come from powerful places". However, I think history was wrong! There was a time when Chhatrapati Shivaji Maharaj proved history wrong and now, there is a time when our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi has shown this world that "Powerful people make places powerful". We are in an era that belongs to 'Jagadguru Bharat'.

With this, I would like to congratulate the Prime Minister and the Finance Minister to have come up with the second batch of Supplementary Demands for Grants with a gross additional expenditure of Rs.3,73,761 crores. The 2021-22 Budget, passed in February 2021, had estimated an expenditure of Rs 34,83,236 crore for the year. With this, there is an increase of 8.6 per cent in expenditure over the Budget estimate. The Indian economy is booming today. There was a period between 2009-14 when the external debt (as per cent of GDP) was 23.9 per cent and today, it has come down to 20.6 per cent. Also, the foreign exchange reserves were at 304.2 billion USD in 2013-14 and now, we have reached the supreme number of 586.1 billion USD, and I am cajoled that we will reach heights under the leadership of our hon. PM Shri, Narendra Modi.

Now, I would quickly brush upon the major proposed expenditures in the second batch of Supplementary Demand for Grants. It has been led by four big-ticket items, such as fertiliser subsidies, pending export promotion incentives, expenditure towards food storage and warehousing, and equity infusion into Air India Assets Holding Ltd (AIAHL). The Ministry of Chemicals and Fertilisers would be given Rs 58,530 crore, and Rs 62,057 crore would be given to the Ministry of Civil Aviation for equity infusion in Air India Assets Holding Ltd for repayment of past dues and liabilities. In addition, Rs 49,805 crore would be provided to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution for meeting the expenditure towards various schemes of food storage and warehousing. The Ministry of Railways will get Rs 20,000 crore under the second tranche of the Supplementary Demand for Grants. This will take the allocation

* Laid on the Table

for the Railways' capital expenditure to more than Rs 2.35 trillion in 2021-22. The increased Budget allocation for Railways also reflects in the contribution it makes to the GDP.

Sir, there was a time when PM Nehru had to import 20 lakh tons of wheat from the US to feed Indians and today, there is a time when under Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana (PMGKAY), 80 Crore Indians are being served with food grains for free. The Government has already incurred an expenditure of nearly Rs.2.60 lakh Crore in PMGKAY Phase I-V and the food grain under Phase V would entail an estimated food subsidy of Rs. 53,344.52 Crore and the total outgo of food grains in Phase V is expected to 163 LMT. The second batch of Supplementary Demands for Grants has proposed Rs 40,170 crore for decentralized procurement of food grains, for additional allocation of food grains under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY). And today, those, who always use the poor people card, are not supporting this allocation. It is saddening! However, I would like to say that today, if there is someone who is working for the poor people of this nation, it is just our Government. Since 2013-14, the Budget for agriculture has increased by more than six times, and similarly, the food production has increased to about 300 million tonnes now from 251 million tonnes in 2015-16. The MSP for paddy has increased 2.4 times since 2013-14, and similarly, the MSP for wheat has increased 1.77 times. Sir, close to 11 crore families have benefited from the PM Kisan scheme, and about 15 lakh crore as institutional credit has been given to the agriculture sector. Also, about 11 crore farmers were issued free soil health cards to avoid indiscriminate use of fertilizers. Today, organic farming covers over 15 lakh farmers. And the Opposition parties say that we don't work for the farmers. If some people did not work for the farmers, they were the people on the other side.

The obsession of the UPA Government with the import of fertilizers, is well known, and we know that Rock Phosphate, which is the key raw material for DAP and NPK fertilisers, is imported excessively. India is 90 per cent dependent on imports. Volatility in international prices due to logistic issues affects the domestic prices of fertilisers. They have never worked to help the farmers and the economy by developing the Indian Fertilizer Industry. However, the Government under the leadership of our visionary PM, Shri Narendra Modi is well intended to work for the framers and the Industry. The Government has

brought Potash Derived from Molasses (PDM) under Nutrient Based Subsidy (NBS) scheme, for the first time since its inception in 2010, to give a push to its manufacturing by Sugar Mills as a by-product. It will reduce India's dependence on 100 per cent import of more than 42 LMT of Mineral-based Potash i.e., MOP which cost around Rs. 7,160 crores annually. Also, the Gorakhpur Fertilizer Plant, which was shut for more than 30 years, has been revived and built at a cost of around Rs. 8600 crores. The Gorakhpur Plant will make available 12.7 LMT per annum indigenous neem coated Urea. We will become Atmanirbhar in fertiliser very soon. The Government has directed to commercially exploit and ramp up the production in the existing 30 lakh MT of Phosphorite deposits which are available in Rajasthan, the central part of peninsular India, Hirapur (MP), Lalitpur(UP), Mussoorie syncline, Cuddapah basin (AP).

We are concerned about the *rojgar* for everyone. Our Government has allocated Rs. 73,000 crore under MGNREGS for 2021-22. It is an increase of Rs. 11,500 crore as compared to the FY 2020-21. More than Rs 4.7 lakh crore has been allocated under MGNREGA in seven years of the Modi Government while Rs 1.75 lakh crore was allocated during 10 years of Congress-led UPA dispensation. And yet, they talk about *rojgar*. However, this is nothing but an oblivious void. They have never worked for the poor people of this nation! They say that Uttar Pradesh is left behind. I would like to say that the Yogi Government has created more jobs in four years than SP and BSP did in 10 years when they were in power! Maybe, they are not able to digest the popularity of Yogi Ji among the people and the work of Yogi Ji. I think everyone remembers the Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojana (ABRY)...it was rolled out during pandemic to generate jobs, with Rs 22,810 crore targeted to be spent till March 31, 2024. This scheme has benefitted 39,72,551 new employees with a total amount of Rs 26,12,10,44,142.

I remember that some people from the opposite side used to criticize Digital India Mission. However, today, I am proud to share that more than 10 crore unorganized workers have registered themselves on the E-Shram portal in less than 100 days. Also, 99.7 per cent of the payment of wages under MGNREGA is being made through e-transfer. This is a befitting reply from the poor of this nation to those who underestimated them.

Sir, now, I will come to a super sensational subject that is the Disinvestment of Air India. I would like to say that we are just rightly orienting the path of the civil

aviation industry of our nation by working on the mistakes made by them. First, in 1953, they nationalised Air India and ruined everything. And second, by 2007, they merged Air India (which flew international flights) with the domestic carrier, Indian Airlines, to reduce losses that were the result of their previous mistakes. How poorly the airline was run could be judged from the fact that it has never made a profit since 2007. In fact, since 2009-10, the Government (and indirectly the taxpayer) has spent over Rs 1.1 lakh crore to either directly make up the losses or raise loans to do so. Besides, as of August 2021, that is before disinvestment, Air India's debt was Rs 61,562 crore. Moreover, every additional day that AI remains operational, the Government would have had suffered a loss of Rs 20 crore, or Rs 7,300 crore per year. And yet, they are giving us lessons on how to run the civil aviation industry. With this privatization, we have revived Air India and have unfurled new opportunities in the civil aviation industry. Now, I think, the next big move of the Government should be the privatization of BSNL.

Other than this, the second batch of Supplementary Demands for Grants has proposed Rs 53,123 crore for payment of pending export incentives/remissions under various export promotion and remission schemes. Sir, India's overall exports (Merchandise and Services combined) in July 2021 are estimated to be USD 54.95 billion, exhibiting a positive growth of 36.19 per cent over the same period last year and a positive growth of 23.24 per cent over July 2019. The FDI into India has reached USD 81.7 billion in FY 2020-21. The World Investment Report 2021, released on June 21 by UNCTAD, states that India was the fifth largest FDI recipient in the world in 2020, with its incoming FDI rising 27 per cent over that in 2019. FDI in India has witnessed a 127 per cent hike in the last 7 years that is, USD 36.05 billion in FY 2013-14 and USD 81.7 billion in FY 2020-21. The GST Collections have reached the supreme number of Rs 1.31 Lakh Crore in November.

Sir, we are well oriented to make this nation, - India, that is Bharat - great again under the leadership of our hon. PM Shri Narendra Modi. With this I would conclude. I would only like to say that 'in retrospect, everyone is wise', but as Prime Minister, Shri Narendra Modi states and I quote: "Good governance, with good intentions, is the hallmark of our Government".

(ends)

*ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, the Budget of 2021-22 was presented when the nation was suffering under the impacts of COVID-19. It promised to equip health sector and revive economic growth. But the Government has failed to achieve both the aims. The actions of the Government have, in fact, weakened the health sector. When the MPLADS fund was cut-short by the Government, crucial local level investment in health infrastructure by the MPs was reduced. This has impacted the rural areas very negatively. This has been reinstated lately, but the amount is very less. In 2011, tarring of 100 metres of road costed only X, but in 2021 this amount has shot up to Y. In this situation, at least two crores per Assembly Constituency is required to meet the basic infrastructure needs of the people by every.MP. I urge upon the Government to take this into account while considering the present Bill.

The unscientific implementation of GST and the monumental failure of Demonetization has destroyed the livelihood of small traders and workers of our country. But the Government has failed completely in resolving any of these issues. The proposed package has failed to bring about any change in their lives. This failure should be addressed urgently.

The Appropriation Bill being in consideration is an extension of a budget that has totally failed the people of India. Not only has it failed to meet the aspirations of our people, but many of the necessary areas are totally ignored by it.

The agriculture is the backbone of our nation. This is true for my Constituency as well. Idukki produces about 60% of all the cardamom produced in the country. It contributes to a large amount of total spices production in the country. However, there is no support price mechanism for spices. Cardamom, pepper and rubber should be included in the list of agricultural crops and provision must be made to make sure that procurement happens at MSP as recommended by CACP. The Government has made no effort to get this done. I would like to express my disapproval and seek a positive intervention in this regard.

The sad plight of plantation labour has been brought to the attention of this House many times by me. Labour leads an extremely difficult life. They have poor access to education, health care and even housing. They are made to live in temporary housing called "layams", which is extremely difficult for them. Some of these "layams" have not been renovated in the last fifty years. How can we allow this state to go on? Their welfare is the responsibility of concerned estates. However, these estates are doing little, citing their financial status. The Central Government should have announced a comprehensive package worth Rs. 1000 crore for this sector in South India, as it did to the States of Assam and West Bengal. It is disappointing to see that precious little is being done in this regard.

The issue of human-animal conflict is a pressing issue. In the last ten years, 40 people were killed and more than 300 people injured in Elephant attacks in my Constituency. There is pending amount to be paid to the victims. Also, considering the climate change and human population pressure in these areas, there should be capital expenditure to ensure that infrastructure is built. Also, the forest department should be funded adequately to ensure that there are enough resources inside the forest so that the animals do not venture outside. I urge upon the Government to look at this serious issue and take steps accordingly.

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act was a landmark legislation that protected the livelihoods of crores of rural people through a rights-based approach. There is plenty of international studies that prove that the scheme helped in the alleviation of poverty. However, the budgets in the last few years have neglected this scheme and its implementation has been blocked by the Government by not spending enough funds. The projects executed under this scheme has a potential to improve the infrastructure and livelihood opportunities of rural poor. The wages should be increased and they should be released on time. More productive works suitable to local conditions must be added and more days of work must be ensured. This should be looked upon with seriousness and funds be released to achieve the aims set by the legislation. I urge upon the Government to release funds immediately.

The ASHA workers, Auxiliary Nurse Midwife and the staff who work under National Health Mission are the people who work on the ground to achieve the

health standard targets set by the Government. The salary of staff nurse in Kerala is Rs. 17,000; Lab technician – Rs. 14,000; Pharmacist – Rs. 14,000; Junior Public Health Nurse – Rs. 14,000; and Nursing Assistant – Rs. 7,000. This is much less compared to the kind of hard work they do. The Centre's share in their compensation must be enhanced at least by 50%. They are paid much less and there is no security for their employment. I urge upon the Government to increase the honorarium and make sure that they are compensated enough to live a life of dignity. They should be skilled and equipped with enough resources on a war footing. I urge upon the Government to ensure that this is done through the funds sanctioned through this Bill.

The road transport has got a big boost in the Budget. A handsome amount is being appropriated through this Bill as well. However, there are a lot of concerns raised alongside. One of them is the status of the important NH-85 that connects Kochi to Dhanushkodi and passes through Idukki. The new alignment under the proposed Greenfield Business Corridor will leave towns like Kolenchery, Muvattupuzha, Kothamangalam, Adimali and Munnar out of it. There is a popular demand that the old alignment be kept as national highways and be developed as 24 meters wide, with four lanes. This demand should be noted by the Minister as we discuss this Appropriation Bill.

Under the PMGSY in phase-3, 1300 kilometres were allotted to the Kerala state. This comes to less than 120 kilometres per district. Under the guidelines of phase-3, the focus is on tarring existing all weather roads, rather than tarring existing earth roads. Under the same guidelines, works with more than 40% of tarring of earthen roads cannot be permissible. In my constituency, more than 500 kilometres of roads can be identified that falls under the underdeveloped category. So, I urge upon the Government to release sufficient funds to tar the earthen roads.

The Bill, in its present format, fails to address the demands that the people have put upon this Government. It fails to satisfy this House that such an expenditure was warranted or is being spent at the best interest of the people of India. I express my strong disapproval of the motion and vote against the passage of this Bill. I urge upon the Government to consider the issues I have raised and make due financial commitment so that these important needs by the people are met.

(ends)

*SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Respected Sir,

About West Bengal

West Bengal has ranked number one in the growth of per capita net state domestic product (at current prices) in 2020-21 as per the RBI handbook of Statistics (Indian Economy 2020-21). Our Government not only believes in economic but also social development and upliftment of every section of society. As per the RBI Handbook of Statistics, the growth of per capita net state domestic product for West Bengal was 7.1% whereas for BJP ruled States like Madhya Pradesh were -4.71 and -6.12%, and for Karnataka, 1.62% and -3.25%.

Criticism of Government and International Ranking

Recently, I saw that Twitter was flooded with post by BJP members that Prime Minister Narendra Modi has topped the list of the 'World's Most Popular Leaders' in the 'Global Leader Approval' Ratings released by the American research company, Morning Consult. The Prime Minister has increased his ranking but what about the country which has been falling in all the global rankings.

Women Safety

हम किसी भी international ranking की बात करे तो हमारे देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। Gender Gap की रिपोर्ट तो खुद world economic forum ने दी है जिनके कार्यक्रमों में भाजपा सरकार भाग लेती है switzerland जाके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वालो के भारत की राजधानी में crime बढ़ता जा रहा और june 2021 तक rape cases saw an increase of 43% from 580 till June 15 last year to 833 this year, molestation jumped by 39 % from 733 to 1,022, kidnapping of women from 1,026 to 1,580, abduction of women from 46 to 159, and dowry deaths from 47 to 56.

I do not understand how you are empowering women and ensuring their safety.

Global Hunger Index (GHI) 2021 has ranked India 101st out of 116 countries. In 2020, India was ranked 94th out of 107 countries. मैं कल social media पे देख रही थी की उत्तर प्रदेश में नमक और दाल के पैकेट बाटें जा रहे थे जिसपे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का चित्र था और उसपे लिखा था की सोच ईमानदार और काम दमदार। अगर ऐसे दमदार काम के बाद भी हम पाकिस्तान से भी पीछे तो ये इस सरकार के failure का सबूत है।

As per the 2021 rankings, Pakistan, Bangladesh and Nepal have fared better than India. India has fallen 28 spots to rank 140th among 156 countries on the World Economic Forum's Global Gender Gap index. Who is going to talk about these rankings?

* Laid on the Table

The Happiness Index of the World Happiness Report (WHR) indicates that India's rank has deteriorated over the years. Starting with rank 111 in 2013, it has consistently been going down and was a dismal 139 in the 2021 report – a dip of 25%.

Economy

Unemployment rate in November 2021 is 7 per cent. Growth in India's goods exports slowed down in November 2021 to 26.49 per cent (year-on-year) totalling \$29.88 billion with items such as gems & jewellery and pharmaceuticals registering a decline.

India's increase in import of goods in November 2021 increased by 57.18 per cent to \$53.15 billion.

I would want to know from the Minister that what is it doing to repair our economy which was already going down even before covid came.

Vaccination and petrol prices

दिल्ली में आप सड़कों पर देखेंगे की हर जगह मोदी जी का प्रचार है की उन्होंने मुफ्त में सबको VACCINE दी है लेकिन इसकी सचाई हम सबको पता है। आपने वैक्सीन तो FREE कर दी लेकिन excise duty के नाम पर जो गरीबों को लूटा गया है की तेल के दाम 100 rs के ऊपर है। बंगाल के चुनाव में home minister ने नारा दिया था की अबकी बार 200 पार , शायद वो तेल की कीमतों में increase की बात कर रहे थे। I would want to know from the Minister that how much excise duty was collected and why are the petrol prices so high and troubling the common man?

Farmers Issue and Protest

The manner in which the Prime Minister announced the withdrawal of farm laws is an indication about how this Government was forced to accept the demand of farmers. Our Chief Minister Mamata Banerjee Ji had supported the farmers since the passing of farm laws. And the way these farmers defeated the BJP, I am sure the people of India will also show them the way.

With these words, I conclude my speech.

(ends)

*SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR): Sir, I thank you for giving me the opportunity to participate in the important discussion. I rise to wholeheartedly support the Supplementary Demands for Grants - Second Batch for the financial year 2021-2022.

When we see India, its progress during the post-pandemic period and compare with the situation in several developed countries, India is far ahead of them. The turn around and the pace at which we are moving fast could be possible because of the visionary and committed leadership of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji.

The tenet of 'Jan Seva Hi Prabhu Sevd' which was propounded by Ramakrishna Paramahansa and Swami Vivekananda always inspired the Prime Minister. It became a driving force in whatever he did. India has administered approximately 134 crore 1,33,88,12,577 total doses of the vaccine so far. India has completed vaccination of 100 crore doses on October 21, 2021, in just about nine months since starting vaccination. This has been a tremendous journey in dealing with COVID-19, especially when we recall how things stood in early 2020. Humanity was dealing with such a pandemic after 100 years and no one knew much about the virus. Hon'ble Prime Minister Modi Ji led from the front in ensuring India took monumental steps to swiftly enhance healthcare in the face of the COVID-19 pandemic. His personal intervention, supervision and leadership at each stage of the Pandemic was visible to the world with his constant interaction with Covid warriors, healthcare workers, scientists and vaccine developers. His Bhagirath effort led to India coming out of the crisis zone.

Unfortunately, some people in responsible positions chose, quite irresponsibly, to put politics above the pandemic and continued to fuel those suspicions into vaccine hesitancy. They seemed to be motivated more by Modi Virodh than Corona Virodh. But the Central government led by PM Narendra Modi Ji adopted a unique approach of communicating directly with the people and building awareness and confidence in the vaccines while continuing to motivate lakhs of our healthcare professionals and scientists. Given the income gaps that persist between rich and poor, many thought that vaccines, the most vital and useful tool in the battle against Covid 19, would also be cornered by a handful and the poor would not be able to access expensive vaccines. To address this issue, the Central government not only took the decision to give Free Vaccines to All above the age of 18+ but even

* Laid on the Table

symbolically sent a strong message when the first person to get the jab of hope was not the President of India or the Prime Minister or the Health Minister or some wealthy businessman but a 34-year-old sanitation worker, Manish Kumar, from Delhi's All India Institute of Medical Sciences (AIIMS). His image of getting the first dose in India was not only a powerful one but in many senses reflected the commitment of the Modi government to democratize the drive. Bharat aaj vaccination banana wala bhi, dene wala bhi, aur duniya ko dene wala bhi desh hai.

Sir, post-pandemic, India has moved at a faster pace than most of the developed countries which are still struggling to recover. Aatmanirbhar Bharat Mission encapsulating major structural reforms continues to play a critical role in shaping India's economic recovery, both through the signalling of business opportunities and expansion of spending channels. Armed with necessary macro and micro growth drivers, the stage is set for India's investment cycle to kick start and catalyse its recovery towards becoming the fastest growing economy in the world. India will continue to be the world's fastest growing major economy, clocking a growth rate of 9.5 per cent this fiscal year and 8.5 per cent in the next, according to the International Monetary Fund (IMF) projections.

Due to the initiatives of Hon'ble Prime Minister Shri Modi Ji, India has leapfrogged towards becoming a global leader in digital payments. Prime Minister's Jan Dhan scheme has enabled millions of unbanked poor families to enter the formal economy with "no-frills" bank accounts. Infrastructure is another area which is always on the top of agenda of our Government because we understand that by creating infrastructure, we are not only creating assets but generating jobs also and providing ways and means for greater connectivity among people. Modi Ji's Government has created massive infrastructure at both rural and urban areas. Our Government has been laying 36km of highways a day on average, compared to UPA's daily count of 8-11km. Installed renewables capacity - solar and wind – has doubled in five years. Currently at about 100 gigawatts, India is on track to achieve its 2023 target of 175 gigawatts. I understand, it is not so easy for the Opposition to digest the pace at which Indian economy is moving under the dynamic leadership of Modi Ji.

Multiple steps taken to give a major boost to Agriculture Farmers have always been the back-bone of our country and our Government is committed to strengthen this back-bone of the country through innovative and solid measures. Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana has given a boost to productivity by ensuring irrigation facilities. The Vision is to ensure access to some means of protective Irrigation to all agricultural farms. Farmers are being educated about modern

irrigation methods to give 'Per Drop More Crop'. Paramparagat Krishi Vikas Yojana has been launched to motivate groups of farmers to take up organic farming. Modi Ji is working on both the fronts of reducing input cost and increasing farmers' income. I will take this opportunity to ask the Opposition parties to introspect why they misled the farmers on the three farm laws. They need to introspect.

Under the leadership of Modi Ji, India has set off on an ambitious mission, a mission to provide electricity to 18,000 villages which were still in darkness after 7 decades of independence. Rural Electrification is happening at a rapid pace, and is being done in an unbelievably transparent manner. Data on villages being electrified is available to the public through a mobile app and a web dashboard. Similarly, Water has for years been a key agenda for Narendra Modi Ji. Jal Jeevan Mission under the Jal Shakti Ministry aims to provide adequate and safe drinking water to each household in rural India via tap connections by 2024, and sets an example for transparency in delivering on its promises by operating a real-time dashboard on the number of household tap-water connections and offering a range of data in this regard.

I am grateful to the Hon'ble Prime Minister for fulfilling each and every demand of my Constituency Jamnagar-Dwarka. Whatever difficulties of the people of my Constituency have been brought to the notice of either the Central Government or the State Government, they have been suitably addressed. I convey my gratitude and the gratitude of people of Jamnagar- Dwarka to the Government and Prime Minister, Hon'ble Shri Narendra Modi Ji for all the development works there. The things that people of India are entitled to, those benefits that they should have received decades ago, had not reached them because of the apathy of previous Non-BJP Governments at the Centre and States. Modi Ji has accelerated the pace of development of India and now the benefits of development are reaching the last man of the society. With these words, I conclude. I reiterate that I support the Supplementary Demands for Grants – Second Batch for the financial year 2021-2022 because this is meant for the benefit of the people of India.

Thank you.

(end)

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी।

... (व्यवधान)

1402 बजे

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS
(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Shall I give the reply? ... (*Interruptions*).

सर, क्या मैं रिप्लाय दूँ ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Yes

... (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I am thankful that you have given me the permission to speak on the subject, that is, Supplementary Demands for Grants. ... (*Interruptions*). The other day when the discussion commenced, many hon. Members spoke on various aspects of the economy, not just confining themselves to the Supplementary Demands for Grants ... (*Interruptions*). I take this opportunity to answer many of the issues raised which pertain to the larger issues of the economy, not just the Supplementary Demands for Grants. ... (*Interruptions*). One particular thing which, of course, I would like to highlight is that many Members had said that this time the Demands is very high. ... (*Interruptions*). Is it because we under-estimated in the BE, and therefore, we have come up with a higher Demands? ... (*Interruptions*). I just want to highlight repeatedly that the total demand is Rs. 3,73,761 crore, of which, Rs. 2,99,243 crore is the additional cash outgo. ... (*Interruptions*). It is also because of the big-ticket expenditure we are going in for. It also involves the amount allocated for Air India which has been mentioned in the Supplementary Demands for Grants.... (*Interruptions*). ... (*Interruptions*). Also, at a time when we are very, very sensitive to the farmers and their requests, and since the international prices of fertilizers have gone up, we had to ensure that the farmers do not suffer because of this. ... (*Interruptions*) Therefore, increase in the subsidy for fertilizer has been provided, which itself is accounting for Rs. 58,430 crore. ... (*Interruptions*).

There are one or two very serious issues which hon. Members have raised during the debate, and because of the fact that they pertain to the Supplementary Demands for Grants, I would like to answer those questions. ...

(*Interruptions*). First of all, I will talk about the additional demand which is being raised ... (*Interruptions*). Even in 2011-12, more than 8.6 per cent of the BE was raised through the Supplementary Demands for Grants for the second and the third batch put together ... (*Interruptions*). In 2012-13, that was about 4.8 per cent ... (*Interruptions*). Additional amounts to the tune of 8.6 per cent in 2011-12 were raised through the Supplementary Demands for Grants, whereas in 2021-22, we have given consideration to the factors like second wave; we extended the food subsidy; there was reduction in the fuel price, which the Central Government has brought in and due to which our revenues have come down to that extent; we have given the fertilizer subsidy which I just mentioned. ... (*Interruptions*).

(1405/AK/SK)

Our additional Demand put together is 9.3 per cent in 2021-2022 BE whilst excluding Railways in the BE it is about 9.6 per cent. ... (*Interruptions*) This is regarding the Supplementary Demand itself. ... (*Interruptions*)

Sir, it was very very disappointing that when hon. Member, Dr. Shashi Tharoor spoke about '*Beti Bachao Beti Padhao*' he came up with a very disheartening and discouraging slogan '*Paisa Bachao Beti Dubao*'. ... (*Interruptions*) If only hon. Member, Dr. Shashi Tharoor, looked into the fundamental data, he will know that so much of good work has happened. ... (*Interruptions*) I will list out a few. ... (*Interruptions*) The latest National Family and Health Survey recorded -- for the first time in the record -- that there are more women in today's India, namely, 1,020 women per 1,000 men. ... (*Interruptions*) This data has come out after two years of research. ... (*Interruptions*) This is the first thing that first time on record we have more women in this country than men. ... (*Interruptions*)

Secondly, 44 crore bank accounts are opened under the Jan Dhan Yojana. ... (*Interruptions*) More than half of it, that is, 24.48 crore are accounts of women. ... (*Interruptions*) Further, 80 per cent of women in India have a bank account today because of Prime Minister's Jan Dhan Yojana. ... (*Interruptions*) The important thing that one has to understand in this is the spread between the rural and urban areas. ... (*Interruptions*) Jan Dhan account holders are both in the rural and urban areas. ... (*Interruptions*) Even better, 70 per cent of all those who have Mudra accounts are women. ... (*Interruptions*) So, because of the

persistent women's led development, we are able to see that women are now included more in bank accounts. ... (*Interruptions*) So, 70 per cent of all the beneficiaries in Mudra Yojana are women. ... (*Interruptions*)

I will also draw the attention of hon. Member, Dr. Shashi Tharoor - - who is not even here -- that because of schemes like '*Beti Bachao Beti Padhao*' the gap between girls and boys in higher educational institutions is narrowing, and as of today 49 per cent of all students in colleges are now girls according to the latest All-India Survey on Higher Education. ... (*Interruptions*) The survey for 2019-2020 has also shown that during the last five years, that is, between 2015-2016 and 2019-2020 there has been a 11.4 per cent growth in student enrolment whereas the female enrolment has been 18.2 per cent. ... (*Interruptions*) It is much higher than the overall average. ... (*Interruptions*) This has to be kept in mind, and not getting into sloganeering without facts being looked into. ... (*Interruptions*)

There were Members saying : "What has happened to people like Nirav Modi who have gone out of this country. What have you got from their assets? They are all defaulters". ... (*Interruptions*) I would like to say that a total of Rs. 13,109.17 crore have been recovered from asset sales of Vijay Mallya, Nirav Modi and Mehul Choksi as of July, 2021 and that is the information from the Enforcement Directorate. ... (*Interruptions*) The latest recovery was Rs. 792 crore from the sale of assets belonging to Vijay Mallya and others on 16 July, 2021. ... (*Interruptions*) Further, Public Sector Banks together have effected a recovery of Rs. 5,49,327 crore over the last seven financial years. ... (*Interruptions*)

(1410/SPR/MK)

So, these people who are defaulters, who have fled the country, we have got their monies back and put it in the public sector banks. ... (*Interruptions*) Therefore, the banks are safer today, and depositors' money is safer in them. I wish, the Opposition understands that this is the effort made by the Prime Minister Modi's Government and it is no good for them to deny that. ... (*Interruptions*)

There were also questions about the finance position of the States. I would like to say that the total transfer to the States in the first eight months of this financial year are already 86.4 per cent of what was provided in the full year of 2019 and 76.8 per cent of what was provided in the full year of 2020-21. ... (*Interruptions*) I also want to say that from the NDRF funds are being provided and an extra Rs.15,000 crore were provided in response to the emergency COVID-19 requirement. ... (*Interruptions*) Sir, I would like to put it on record that the financial position of the States is also reflected in the fact that the overall cash balance of States as on 0th November 2021 was Rs.3.08 lakh crore approximately; it is fairly a comfortable position. ... (*Interruptions*) I am happy that all of us are working together to keep the finances of the States in a comfortable position. States are having substantial cash balance. There are only a few exceptions; out of 28 States, only two States are having negative cash balance. ... (*Interruptions*)

I want to put it on record by responding to the questions asked by the hon. Member Shri Dayanidhi Maran as regards the disinvestment in Air India. He spoke about the sale of Air India for about Rs.18,000 crore. ... (*Interruptions*) However, the value realisation for this deal is not what he is talking about. Through this deal, Rs.15,300 crore of Air India's debt will be paid for by the acquiring company, and this won't be a further burden on the taxpayers. ... (*Interruptions*) The winning bid is also significantly higher than Rs.12,906 crore, which is the reserve price set by the Government for the sale of the company.

I also want to highlight that Dayanidhi Maran *ji* and his elder brother had sold SpiceJet for just Rs.2 per share in 2015. ... (*Interruptions*) According to the share price at that time of the SPA, the stake was worth Rs.765 crore, which was sold for Rs.2 per share. At least, he should then realise what it is when we sold Air India at enterprise value. He should know, and he should in fact

appreciate the point having himself at a personal level been involved with the sale of a particular airline and at that rate. ... (*Interruptions*) At that time, SpiceJet reportedly had debts, liabilities and outstanding of Rs.3,500 crore with immediate payables of Rs.2,200 crore, and the book value of the company was minus 24 per cent. ... (*Interruptions*)

So, the situation of an airline company which does not make profit, and then trying to sell it, and selling it at a value of Rs.2 per share, I am sure, hon. Member, Shri Dayanidhi Maran will appreciate and know how companies are being sold because he himself sold his company at Rs.2 per share when it was in minus 24 per share valuation. ... (*Interruptions*)
(1415/UB/SJN)

That comes to Rs. 13,500 crore as the principal amount and the rest as interest. I request the hon. Members to pay attention to this one. I would like to say that the tax payers of today are paying for the subsidy dished out to consumers more than a decade ago by the UPA Government, and they will continue to pay for the next five years as the redemption of the bond continues until 2026. ... (*Interruptions*)

What I want to draw your attention to, hon. Chairman Sir, is that even the former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, in an address to the nation on 4th June, 2008, said, "However, I would like the nation to remember that issuing bonds and loading deficits on oil companies is not a permanent solution to this problem. We are only passing on our burden to our children who will have to repay this debt". ... (*Interruptions*)

डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी माना था कि ऑयल बॉन्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं और वे ग्राहकों को सब्सिडी नहीं दे रहे हैं।...(*व्यवधान*) सारे बोझ को ऑयल बॉन्ड्स और ऑयल कंपनी के ऊपर डाल दिया गया।...(*व्यवधान*) भविष्य में आने वाली जेनरेशन के ऊपर वह बोझ पड़ेगा, इस विषय के बारे में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था।...(*व्यवधान*) जब हम कहते हैं कि आज तक हम उसकी भरपाई कर रहे हैं, तो इनकी समझ में आना चाहिए कि इन्होंने ऑयल प्राइस सब्सिडी को नहीं बढ़ाया, मगर इन्होंने उसका पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश की, जो गलत था, हम आज तक उसकी भरपाई कर रहे हैं।...(*व्यवधान*) And this speech of Dr. Manmohan Singh came after the bond issue was made. So, I want that to be brought on the record. ... (*Interruptions*)

Finally, there was also enough concern being expressed by the hon. Members on inflation. I want to underline the fact that for more than five full

years, the UPA Government ran their Government with double-digit inflation and they did not do anything about it. Today, even when inflation is contained well within six percent, which is a permitted limit, they seem to be talking about price rise. Yes, for edible oil and things like that, we are taking measures through the EGOM which is Empowered GOM for taking care of essential goods. We will attend to the problem of edible oil price and also some of the essential edible items. But, Sir, because the debate went beyond what was necessary in terms of the Supplementary Demands for Grants, the hon. Members have every right to raise the issues but I wanted to put my response on record. ... (*Interruptions*)

With this, I request the hon. Members and the entire House to pass the Supplementary Demands for Grants.

(ends)

HON. CHAIRPERSON (DR. (PROF.) KIRIT PREMJI BHAI SOLANKI): I shall now put the Supplementary Demands for Grants – Second Batch for the year 2021-22 to the vote of the House.

The question is:

“That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2022 in respect of the heads of demands entered in the Second column thereof against Demand Nos. 1, 3, 4, 6 to 8, 10 to 12, 15, 17 to 20, 22, 23, 25 to 31, 33 to 35, 40, 44 to 51, 53, 54, 59 to 65, 67 to 70, 73, 75 to 78, 81, 84 to 88, 90, 92 to 99 and 101.”

The motion was adopted.

(1420/YSH/KMR)

विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक

1420 बजे

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी) : आइटम नंबर 20– माननीय वित्त मंत्री जी।
... (व्यवधान)

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2021-2022.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुरःस्थापित कीजिए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce the Bill.

... (*Interruptions*)

माननीय सभापति : अब आइटम नंबर – 21, माननीय वित्त मंत्री जी।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

“That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2021-2022, be taken into consideration.”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed.”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

**MOTION RE: REFERENCE OF BIOLOGICAL
DIVERSITY (AMENDMENT) BILL TO JOINT COMMITTEE**

1424 hours

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 21ए, माननीय मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव जी।

THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE, AND
MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BHUPENDER YADAV):

Sir, I beg to move:

“That the Bill further to amend the Biological Diversity Act, 2002 be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of the following 21 Members from this House:-

1. Dr. Sanjay Jaiswal
 2. Ms. Diya Kumari
 3. Dr. Heena Vijaykumar Gavit
 4. Smt. Aparajita Sarangi
 5. Shri Raju Bista
 6. Shri Pallab Lochan Das
 7. Shri Santosh Pandey
 8. Shri Prathap Simha
 9. Shri Jugal Kishore Sharma
 10. Shri Brijendra Singh
 11. Shri Ajay Tamta
 12. Shri Jagdambika Pal
 13. Shri Gaurav Gogoi
 14. Ms. S. Jothimani
 15. Shri A. Raja
 16. Dr. Kakoli Ghosh Dastidar
 17. Shri Sridhar Kotagiri
 18. Shri Prataprao Jadhav
 19. Shri Sunil Kumar Pintu
 20. Shri Achyutananda Samanta
 21. Shri Ritesh Pandey
- and 10 Members from the Rajya Sabha;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of Members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the last day of the first week of next Session;

that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committee shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House names of the Members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee.”

I have obtained the consent of the Members to serve in the Committee.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि जैव विविधता अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को भेजा जाए जिसमें इस सभा के निम्नलिखित 21 सदस्य होंगे।”

1. डॉ. संजय जायसवाल
2. सुश्री दिया कुमारी
3. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
4. श्रीमती अपराजिता सारंगी
5. श्री राजू बिष्ट
6. श्री पल्लव लोचन दास
7. श्री संतोष पान्डेय
8. श्री प्रताप सिम्हा
9. श्री जुगल किशोर शर्मा
10. श्री बृजेन्द्र सिंह
11. श्री अजय टम्टा

12. श्री जगदम्बिका पाल
 13. श्री गौरव गोगोई
 14. सुश्री एस. जोतिमणि
 15. श्री ए. राजा
 16. डॉ. काकोली घोष दस्तीदार
 17. श्री श्रीधर कोटागिरी
 18. श्री प्रतापराव जाधव
 19. श्री सुनील कुमार पिन्टू
 20. प्रो. अच्युतानंद सामंत
 21. श्री रितेश पाण्डेय
- और राज्य सभा से 10 सदस्य;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी;

कि अन्य मामलों में संसदीय समिति से संबद्ध इस सभा के कार्य संचालन के नियम ऐसे परिवर्तन तथा आशोधनों के साथ लागू होंगे जैसा कि अध्यक्ष निर्धारित करें; और

कि यह सभा राज्य सभा को सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सहभागिता करे तथा संयुक्त समिति के लिए नियुक्त होने वाले सदस्यों के नामों की सूचना इस सभा को दे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

(1425/RPS/RCP)

... (व्यवधान)

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी) : सभा की कार्यवाही दो बजकर पैंतालीस मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

1425 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजकर पैंतालीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

(1445/RK/SPS)

1445 hours

*The Lok Sabha re-assembled at forty-five minutes past
Fourteen of the Clock.*

(Dr. Kirit P. Solanki in the Chair)

HON. CHAIRPERSON: Item No. 21B. Hon. Minister, Shri Kiren Rijiju.

ELECTION LAWS (AMENDMENT) BILL

1445 hours

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, I beg to move:

“That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950 and the Representation of the People Act, 1951, be taken into consideration.” ... *(Interruptions)*

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Sir, you cannot bring this Bill ... *(Interruptions)*

1446 hours

(At this stage, Sushri Mahua Moitra, Shri Gaurav Gogoi, Shrimati Kanimozhi Karunanidhi, and some other hon. Members came and stood near the Table.)

माननीय सभापति : मंत्री जी, क्या आप बिल के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे?

श्री किरन रिजिजू : सर, हम इस सदन में आज इलेक्शन लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2021 लेकर आए हैं। इसमें कुछ प्रावधान लेकर आए हैं। ... (व्यवधान) भारत का जो चुनावी प्रोसेस है, इलेक्शन करने का जो तरीका है, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हम जो चुनाव कराते हैं, उसमें कई अच्छी चीजें सामने आने वाली हैं। ... (व्यवधान) मैं खासकर तीन पाइंट्स बताना चाहता हूँ। अभी तक का जो इलेक्शन लॉ है, अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है, जो प्रावधान है, उसमें कुछ डिस्पैरिटी है, कुछ कमियां हैं। उनको दूर करने के लिए सरकार ने इलेक्शन कमीशन के साथ तालमेल करके, इलेक्शन कमीशन से जो रिकमेंडेशंस आई हैं, उनको मिलाते हुए, हमने कुछ चेंजेस इस अमेंडमेंट के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। ... (व्यवधान)

हम सब लोग जानते हैं कि संविधान के मुताबिक जब 18 साल पार हो जाते हैं तो आपका वोटिंग का राइट होता है। लेकिन अभी जो प्रावधान है, उसमें 18 साल क्रॉस होने के बाद भी आप वंचित रहते हैं... (व्यवधान) इस सिस्टम में 1 जनवरी, जो क्वालिफाइंग डेट है, वह पूरे साल में एक ही क्वालिफाइंग डेट दी गई है। उस क्वालिफाइंग डेट में जो आते हैं, वह ठीक है, लेकिन उसके बाद पूरे साल में जो होते हैं, वे रह जाते हैं और वे वंचित हो जाते हैं। 18 साल होने के बाद इस क्वालिफाइंग डेट को कैलेण्डर ईयर में 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर चार क्वालिफाइंग डेट्स कर दी गई हैं। ... (व्यवधान)

इसके अलावा हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, वह जेण्डर न्यूट्रल नहीं था। इसका मतलब है कि एक इंसान किसी सर्विस में काम करता है और ओरिजनल वोटिंग की जगह पर उसका नाम है, अगर वह उससे अलग जगह जाता है तो सर्विस वोटर कहलाता है। ... (व्यवधान) वहां पर लिखा हुआ है – वाइफ, यानी हसबैंड का कोई प्रावधान नहीं है। वहां पर वाइफ लिखा हुआ है। सैक्शन 20 के सब-सैक्शन 6 में रिप्रेजेंटेशन पीपुल्स एक्ट में जो वाइफ लिखा हुआ है, इसमें उसकी जगह स्पाउज़ लिखने का प्रावधान किया गया है। जब इस पर चर्चा होगी तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ... (व्यवधान)

सर, इसके बाद प्रिमाइसिस की बात है। इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए जो जगह चाहिए होती है, उस प्रिमाइसिस को एक्वायर करने का प्रावधान है। इसमें उसको थोड़ा एक्सपैण्ड किया गया है। मैं उसके बारे में भी माननीय सदस्यों को विस्तार से बताऊंगा। ... (व्यवधान) आखिर में हम लोग सब चाहते हैं कि देश में जो इलेक्टोरल रोल है, चुनावी सूची है, वह अच्छी हो, सही हो, जैनुइन हो। इलेक्शन कमीशन भी यही चाहता है। इसमें एक प्रावधान डाला गया है कि एक नागरिक के पास या ऑर्डिनरी रेजिडेंट के पास आधार कार्ड है, उसको इलेक्टोरल रोल के साथ लिंक करने का प्रावधान रखा गया है।... (व्यवधान)

(1450/RAJ/PS)

यह वॉलन्टरी है, कम्पलसरी नहीं है, मैनडेट्री नहीं है।... (व्यवधान) सरकार बहुत ही अच्छा चुनाव सुधार का जो प्रपोजल लेकर आई है, उसका समर्थन पूरा सदन करेगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। बाद में माननीय सदस्य जब कहेंगे, तो मैं इस पर पूरे क्लैरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन के साथ बताऊंगा कि यह चुनाव सुधार देश के लिए कितना जरूरी है। धन्यवाद।... (व्यवधान)

(ends)

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी) : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधयेक पर विचार किया जाए।”

1450 बजे

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, आज सुबह हम ने सरकार से एक दरखास्त की थी, यह बिल आज इंट्रोडक्शन हो रहा है, आज यह बिल पारित हो रहा है, आप लोग इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं... (व्यवधान) अगर यह बिल महत्वपूर्ण है, तो इतनी जल्दबाजी में पास करने की क्या जरूरत है? ... (व्यवधान) हम ने यह भी मांग की थी कि इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए... (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): The Government has not generated enough public opinion. ... (*Interruptions*) Public opinion should be generated fully. This Bill should be discussed in the House after some time, after getting the nod from ... (*Interruptions*)

श्री किरिन रिजीजू : सर, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात का क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ कि हमारे विपक्ष के नेता ने स्टैंडिंग कमेटी के बारे में कहा है... (व्यवधान) यह स्टैंडिंग कमेटी से ही रेकमेंड हो कर आया है... (व्यवधान) मैं सदन की जानकारी के लिए स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ना चाहता हूँ।

The Departmentally related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice in its 105th Report has stated that the Committee is of the view that linking of Aadhar number with Electoral Roll will purify electoral rolls and consequently reduce electoral malpractices. ... (*Interruptions*) Accordingly, the Committee has directed that the relevant laws, in this regard, should be amended at the earliest and Action Taken Report is required to be forwarded to the Committee. ... (*Interruptions*) यह पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें ऑल पार्टी के माननीय सदस्य हैं, वहीं से ये रेकमेंडेशंस आए हैं।

1452 बजे

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, यह जो कांग्रेस है, यह केवल इंस्टीट्यूशन को ...(अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) करती है...(व्यवधान) इसने इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था को ...(अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) दिया...(व्यवधान) सभापति महोदय यदि आपको ध्यान हो, तो ...(अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वे कांग्रेस के माननीय सांसद बने और कांग्रेस ने उनको अपना मंत्री बनाया...(व्यवधान) इसी कारण से वह इलेक्शन कमीशन को ...(अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) रखना चाहती है...(व्यवधान) हमारी सरकार जो एक बिल लेकर आई है, एक सीरियस रिफॉर्म लेकर आई है, उसको यह बर्बाद करना चाहती है...(व्यवधान) सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस हमेशा क्लेम करती है कि हम आधार लेकर आए हैं...(व्यवधान) इन्होंने आधार का पैसा...(व्यवधान) बिना किसी कानूनी जामा के पहना दिया...(व्यवधान) अगर आज हम आधार को इलेक्टोरल रोल के साथ जोड़ रहे हैं, तो कौन-सा अन्याय कर रहे हैं? ...(व्यवधान) क्योंकि इनको बांग्लादेशियों को बनाना है...(व्यवधान) इस सदन में ऐसा हुआ है कि ...(अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) नेपाल के नागरिक थे, वे यहां के माननीय सांसद हो गए...(व्यवधान) इस आधार के बाद कांग्रेस न बांग्लादेशी को बना सकती है, न नेपाली को बना सकती है और न किसी अन्य को बना सकती है...(व्यवधान) वोट बैंक की राजनीति के कारण सारी पॉलिटिकल पार्टिज टीएमसी हो या कांग्रेस हो, ये सभी लोग केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं...(व्यवधान) दूसरा सवाल यह है कि जो पोलिंग बूथ्स हैं, कई जगह मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम वे मदरसे में हो जाते हैं, मैक्सिमम मस्जिद में हो जाते हैं और उसके लिए इलेक्शन कमीशन के पास कोई अख्तियार नहीं था। इसीलिए सरकार यह संसोधन लेकर आई है...(व्यवधान) हम इस बिल का समर्थन करते हैं और सदन से आग्रह करते हैं कि बांग्लादेशी को, विदेशी को यहां का वोटर न बनने दिया जाए...(व्यवधान) इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था में कभी ...(अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) जैसा उदाहरण न हो कि वह कांग्रेस का मंत्री हो जाए, कभी मुख्यमंत्री हो जाए, इसलिए पूरा सदन इसका साथ दे...(व्यवधान) इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।

(इति)

(1455/SMN/VB)

1455 hours

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, this is the Bill whereby the entire democracy is being taken away in this way. This Bill needs a discussion.

Sir, I will tell you. Last week, this Minister of Law and Justice invited me and also all the Members of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice. At that time, he committed that it would be sent to the Standing Committee. Now, this is his master plan. He is killing. ... *(Interruptions)* He is killing. ... *(Interruptions)* He is killing the entire thing.

(ends)

1455 hours

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): माननीय सभापति महोदय, मैं शिव सेना की तरफ से इस बिल का विरोध कर रहा हूँ... (व्यवधान) जिस जल्दबाजी में यहाँ पर इस बिल को पेश करने की कोशिश की जा रही है, परम् पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की कृपा से हम सभी लोगों को मतदान का पवित्र अधिकार प्राप्त हो चुका है, मतदान सूची को आधार से लिंक करना और जल्दबाजी में उसे पास करना सही नहीं है... (व्यवधान) इस पर सही तरीके से बहस होनी चाहिए। इस पर सभी लोगों को अपने-अपने विचार व्यक्त करने की आवश्यकता है... (व्यवधान)

(ends)

1456 hours

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): I have only two-three important questions to ask the Government. The Bill was introduced today. What is the tearing hurry? ... *(Interruptions)*. In the speech, Mr. Nishikant Dubey talked about Bangladeshis. In the newspapers, it is said that only the Congress wants Bangladeshis. I have a humble question to the BJP. There is an allegation against the BJP that one of the Ministers is a Bangladeshi, an allegation in West Bengal. That must be verified when he talks about other people.

The other thing is that they have talked about electoral reforms. If the hon. Minister wants electoral reforms, he should take this Bill back, bring a comprehensive Bill covering entire electoral reforms, talk about the women's reservation Bill, electoral bonds, इसके साथ महिला रिजर्वेशन का बिल भी साथ लाएं, हम समर्थन करेंगे और यह बिल पास करेंगे... (व्यवधान)

So, they should take this Bill back. ... *(Interruptions)*

(ends)

1457 hours

SHRI LAVU SRI KRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, this Bill needs to be discussed. Yes, we very much welcome the gender neutrality which they have taken up in this Bill. At the same time, giving opportunity for four times to enrol themselves as voters is a good thing. ... (*Interruptions*)

But still Sir, we have experienced where 30 lakh people have already been seeded. What had happened in Telangana and Andhra Pradesh in 2015-16? In the Telangana Elections, 30 lakh people could not vote. ... (*Interruptions*) And in Andhra Pradesh, what happened was because of seeding of Aadhaar and this data together, the previous Government could go ahead and make sure whom to be given what and whom to be taken out. ... (*Interruptions*)

So, I request the Minister again to come with a comprehensive Bill so that proper discussion can happen in the House. ... (*Interruptions*)

(ends)

1458 hours

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): माननीय सभापति जी, जैसा कि हम सभी लोग यह मानते हैं कि इस बिल पर कायदे से चर्चा होनी चाहिए और सभी को इस पर बोलने के लिए एक मौका मिलना चाहिए था।... (व्यवधान) जिस हिसाब से इसको सदन में बुलडोज किया जा रहा है, यह कहीं न कहीं हमारी संसदीय परम्पराओं के खिलाफ है। इस बिल में कुछ मुद्दे हैं, जिन पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। ... (व्यवधान)

मान्यवर, इस बिल के जरिए हमारे देश में आधार के साथ वोटर लिस्ट को लिंक करने की बात की जा रही है।... (व्यवधान)

(ends)

1459 hours

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Thank you Sir.

On behalf of my Biju Janata Dal Party, I appreciate the way the hon. Minister said that there will be four phases of qualification and it will be gender neutral. But at the same time, this is not the proper decorum. This is not the proper way to pass any Bill. It was supposed to be introduced today in this House. Today, the House is in a very disturbed way. This is not the proper time. It should be debated. It should be discussed by all parties and then only, considered to be passed. (ends)

1459 hours

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I stand here to oppose the Bill. This Bill violates the basic structure of the Constitution. In the Kesavananda Bharti case, it was clearly said that democracy is a part of the basic structure. This Government is taking away the autonomy of the Election Commission. An EPIC card is issued through a Constitutional process by a Constitutional Authority.

(1500/SNB/PC)

We have no right whatsoever to indulge in it. By bringing this Bill and making it a law, the Government is interfering in the working of the Election Commission ...

(Interruptions)

(ends)

1500 hours

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I rise to oppose this Bill. Today, in the morning, at the time of introduction of this Bill also I opposed it on constitutional grounds. Now, my opposition is to the way by which this Bill is being passed. ... (Interruptions) The Bill has been introduced only today. The hon. Members of this House are not getting the opportunity to move their amendments. This is our democratic right ... (Interruptions) It is the democratic right of a Member to propose and move amendments. It is quite unfortunate that in the parliamentary system of democracy, the Members of the House are not being allowed to move the amendments. Then, what is parliamentary democracy? ... (Interruptions)

(ends)

1501 hours

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, I vehemently oppose this Bill ... (Interruptions) It is a ... (Not recorded) for the entire Legislature. This is never heard in the history of parliamentary democracy ... (Interruptions)

(ends)

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी) : माननीय मंत्री जी – आप बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री किरिन रिजीजू : माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ। ... (व्यवधान) हम Election Laws (Amendment) Bill लेकर आए हैं। ... (व्यवधान) आपने हमें इस बिल को यहां इंट्रोड्यूस करने और इस पर कंसीड्रेशन का मौका दिया। ... (व्यवधान) यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, जिस पर हम चाहते थे कि सब मेंबर्स चर्चा में हिस्सा लें और अपना मत दें। ...

(व्यवधान) पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है, उसके तहत सारी विपक्षी पार्टियों के नेता अगर इस बिल में अपना योगदान देते, इस पर अपने व्यूज देते और चर्चा करते तो इससे बहुत अच्छा संदेश जाता। ... (व्यवधान)

एक तरफ तो ये लोग हाउस में हंगामा कर रहे हैं और ठीक से चर्चा नहीं होने दे रहे हैं, फिर सरकार से कहते हैं कि चर्चा नहीं हो रही है। ... (व्यवधान) हम तो चर्चा चाहते हैं, इसीलिए तो यह बिल लेकर आए हैं। ... (व्यवधान) हम लोग चर्चा चाहते हैं, बहुत ही शांत वातावरण में चर्चा होनी चाहिए। ... (व्यवधान) इस वक्त ये लोग हंगामा कर रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। ... (व्यवधान)

सर, यह इम्पॉर्टेंट बिल है। ... (व्यवधान) चुनाव सुधार की प्रक्रिया को हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार के बीच में है। ... (व्यवधान) जरूरत पड़ने पर राज्य सरकारों के बीच भी लगातार चर्चा की यह प्रक्रिया चलती आ रही है। ... (व्यवधान) कई सालों से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और लॉ-मिनिस्ट्री के बीच कई चर्चाएं हुई हैं। ... (व्यवधान) बहुत इंटेंसिव डिस्कशन होने के बाद आज यह बिल हम यहां लेकर आए हैं। ... (व्यवधान) मैं जब कंसीड्रेशन की लीव ले रहा था, तब मैंने इस बात का जिक्र किया था। ... (व्यवधान) विपक्षी पार्टियों के हमारे कुछ नेता कह रहे हैं कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए। ... (व्यवधान) मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूं कि इस विषय पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में बहुत व्यापक रूप से चर्चा हो चुकी है। ... (व्यवधान) पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में सब पार्टियों के सदस्य होते हैं और वहां दलगत राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा होती है। ... (व्यवधान) पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने यूनेनिमसली रिक्मनडेशन दी है। ... (व्यवधान) मैं देश के लिए इस सदन के माध्यम से इसे पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ... (व्यवधान) पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कहती है – the Committee is of the view that linking of Aadhar Number with electoral roll will purify electoral rolls and consequently reduce electoral malpractices. Accordingly, the Committee has directed that relevant laws in this regard should be amended at the earliest and Action Taken Report is required to be forwarded to the Committee. हम इसे अपनी मर्जी या डिक्टेटोरियल तरीके से नहीं लाए हैं। ... (व्यवधान) व्यापक चर्चा करके ही इस विषय को आज सदन में लाया गया है। ... (व्यवधान) सबसे पहले वर्ष 1988 में जब 61वां कांस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उस समय वोटिंग राइट के लिए आयु 21 वर्ष थी, जिसके बाद उसे 18 वर्ष किया गया था। ... (व्यवधान) जब 18 वर्ष का प्रावधान किया गया था, तब उसमें एक गैप, एक लैकूना रह गया था। ... (व्यवधान) इसकी वजह से 1 जनवरी को अगर कोई इससे पार हो जाता है, उन्होंने अपना नाम इलेक्टोरल रोल में दर्ज नहीं कराया, तो पूरे साल भर के लिए उसके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। ... (व्यवधान)

(1505/IND/RU)

इसका मतलब हम जो चार क्वालीफाइंग डेट्स दे रहे हैं, उनके अनुसार साल में जब भी 18 साल की आयु पूरी होती है, वह तुरंत इलेक्टोरल रोल में अपना नाम दर्ज कर सकता है और संविधान में दिए गए वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकता है।

महोदय, जेंडर न्यूट्रल पर बोलना चाहता हूं... (व्यवधान) आज से पहले यदि कोई दूसरी जगह पर पोस्टेड है और वोट डालना चाहता है, यदि वह पुरुष है, तो उसकी वाइफ उसकी जगह पर वोट डाल सकती है, लेकिन यदि कोई महिला किसी दूसरी जगह पोस्टेड है, तो उसके हरबैंड को वोट डालने का प्रावधान नहीं था। इसे जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है। इसे सैक्शन 20, वर्ष 1950 के पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में, 'the wife' की जगह 'the spouse' कर दिया गया है और जहां 'if she' लिखा है, वहां 'if such spouse' करके अमेंडमेंट लाया गया है।... (व्यवधान) इसके बाद चुनाव के लिए जगह को भी चिह्नित करना पड़ता है। स्कूल, कम्युनिटी बिल्डिंग लेने के लिए रिक्विजिशन करनी पड़ती है। सैक्शन 160, वर्ष 1958 के पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के पुराने प्रावधान में चेंज किया है, जिसे मैं पढ़ना चाहता हूं। Sub-Section 1 (a) of Section 160 says:

“Any premises are needed or are likely to be needed for the purpose of being used as polling stations, for counting, for storage of ballot boxes, voting machines including voter verifiable paper audit trail and poll related material after a poll has been taken, accommodation for security forces and polling personnel.”

चुनाव के लिए जरूरत के हिसाब से -

“provided that such premises shall be requisitioned after the issuance of notification of the Election Commission under Section 30 for such election till the date notified under clause 'e'.”

यानी कि जब तक इलेक्शन नोटीफाई नहीं करेंगे, तब तक मर्जी से इलेक्शन अधिकारी उस जगह को रिक्विजिशन नहीं कर सकते हैं।... (व्यवधान) इन्होंने पुत्तास्वामी जजमेंट को कोर्ट करके 'आधार' के साथ इलेक्टोरल रोल के लिंक का मुद्दा उठा भी है।... (व्यवधान) मैं मानता हूं कि इन्होंने बिल के प्रावधान को ठीक से नहीं पढ़ा है या समझने के बाद जानबूझ कर भी समझ नहीं रहे हैं, मैं कह नहीं सकता हूं। लेकिन जिस तरह से विरोध का स्वर उठा है, यह ठीक नहीं है। पुत्तास्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि “Right to privacy is a fundamental right.” इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि -

“Permissible limits for invasion of privacy, namely, there should be existence of law, legitimacy of interest and such law should pass the test of proportionality.”

इन तीनों के बारे में मैं शार्ट में जस्टीफाई करके बताना चाहता हूँ... (व्यवधान) सबसे पहले ‘एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ’ होना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसलिए हम आज यह लॉ लेकर आ रहे हैं, to justify the Supreme Court ruling. दूसरा लेजिटीमैसी आफ इनटरेस्ट इसलिए है कि

Section 17 of RP Act says:

“No person shall be entitled to be registered in electoral roll for more than one constituency.”

मल्टीपल नाम को हटाने के लिए यह लेजिटीमैसी आफ इनटरेस्ट इसमें जुड़ा हुआ है और साथ में test of proportionality के लिए हम जो प्रावधान ला रहे हैं, वह जनता के इनटरेस्ट में है, वोटर के इंटरेस्ट में है और देश में साफ सुथरे चुनाव की दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं सदन से अनुरोध करता हूँ कि इस विधेयक का सब समर्थन करें।... (व्यवधान)

(इति)

(1510/KDS/SM)

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी) : प्रश्न यह है :

“कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

“कि खण्ड 2 से 7 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

... (व्यवधान)

SHRI KIREN RIJJU: Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed.”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

... (व्यवधान)

1512 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 21 दिसम्बर, 2021 / 30 अग्रहायण, 1943 (शक)

के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।